RNI NO. CHHHIN/2022/83778

न्यूज रूटीन

मासिक, बलौदाबाजार से प्रकाशित

वर्ष : 02 अंक : 11 मासिक, बलौदाबाजार, नवम्बर 2023 E-mail: newsroutine6@gmail.com पृष्ठ : 16 मूल्य : 15 रू.

74 सीटों पर मतदान का बना रिकार्ड

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव-2023 में मतदान की तस्वीर साफ होते ही सियासी गलियारों में चर्चाएं गर्म है। पहले और दूसरे चरण के मतदान के बाद प्रदेश की 90 सीटों पर कुल 76.31 प्रतिशत मतदान हुआ है। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले हालांकि मतदान प्रतिशत 0.57 प्रतिशत कम है, लेकिन प्रदेश की 74 ऐसी सीट हैं, जहां वर्ष 2018 के मुकाबले अधिक मतदान हुआ है।

इन विधानसभा सीटों पर ज्यादा मतदान की कई संभावनाएं तलाशी जा रही है। राजनीतिक गलियारों में ज्यादा मतदान होना बेहतर संकेत माना जाता है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इससे कई समीकरण बन सकते हैं, जिन सीटों पर ज्यादा मतदान हुआ है वहां दोनों पार्टियां इसे अपने लिए बेहतर संकेत मान रही है।

64 हजार अधिक महिलाओं ने किया मतदान

साल-2023 में एक बार फिर महिलाओं ने बाजी मारी है। महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले 64 हजार ज्यादा मतदान किया है। 2023 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश में कुल 76.31 प्रतिशत मतदान हुआ है, जिसमें 78 लाख 12 हजार 631 महिला व 77 लाख 48 हजार 612 पुरुषों ने मतदान किया। पुरुषों के मुकाबले महिला मतदाताओं की संख्या 64,019 अधिक रही।

छह विधानसभा सीटों पर 85 प्रतिशत से अधिक मतदान

प्रदेश के छह विधानसभा सीटों पर 85 प्रतिशत से अधिक मतदान दर्ज किया गया है। इनमें लूंड्रा में 85.03 प्रतिशत, खरसिया में 86.67 प्रतिशत, धर्मजयगढ़ में 86.00 प्रतिशत, बिंद्रानवागढ़ में 86.02 प्रतिशत, सिहावा में 87.64 प्रतिशत व कुरूद में सबसे ज्यादा 90.17 प्रतिशत मतदान शामिल हैं।

रायपुर की महिला मतदाताओं ने किया निराश

रायपुर के सात विधानसभा सीटों पर चार विधानसभा सीटों पर 2018 के मुकाबले कम मतदान की वजह से प्रत्याशी भी आश्चर्य है। इनमें रायपुर की महिला मतदाताओं से निराशा हाथ लगी है। रायपुर पश्चिम, रायपुर उत्तर, रायपुर ग्रामीण और रायपुर दक्षिण के कुल मतदाताओं में महिला मतदाताओं की संख्या कम रही है।

चुनावी रण में कर्ज माफी और महिलाओं को सीधे नकद की घोषणा रही प्रभावी

महिला बनाम किसान के मुद्दों की यह चुनावी लड़ाई परिणाम

रायपुर। चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इस बार मतदान के लिए मतदाताओं के समक्ष दो ही मुद्दे अधिक प्रभावी रहे। इनमें से एक भाजपा की महतारी वंदन योजना, जिसमें महिलाओं के खाते में सीधे नकद मिलेगा और दूसरा, कांग्रेस की कर्ज माफी की गारंटी, जिसमें किसानों का कर्ज माफ होगा। मतदान का समीकरण बनाने में मतदाताओं की दृष्टि इन्हीं दो योजनाओं के इर्द-गिर्द घूमती रही।

अनुमान है कि महिला बनाम किसान के मुद्दों की यह चुनावी लड़ाई परिणाम में भी असर दिखाएगी। भाजपा ने कांग्रेस के कर्ज माफी के मुकाबले किसानों के दो वर्ष का बकाया बोनस देने और कांग्रेस ने भाजपा के महतारी वंदन योजना की तुलना में गृह लक्ष्मी योजना शुरू करने का वादा किया है, मगर ये मुद्दे मतदाताओं की जुबान पर प्रभावी तरीके से नहीं टिक पाए।

महिलाओं के इस योजना से कम से कम कुछ खर्च तो निकलेगा

नईदुनिया ने मतदान केंद्रों से वोट देकर निकल रहे लोगों से बात करके ये जानना चाहा कि उन्होंने किन मुद्दों के आधार पर वोट डाला है। रायपुर-पश्चिम विधानसभा क्षेत्र स्थित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय में विमला नामक एक महिला ने कहा कि महिलाओं को हर महीने एक हजार रुपये देने की इस योजना से कम से कम कुछ खर्च तो निकलेगा।

इसी तरह शहर के निवेदिता स्कूल के बूथ में पहुंचीं सावित्री नामक महिला ने भी महतारी वंदन योजना को श्रेष्ठ गारंटी बताया। वहीं, शहर से कुछ दूर रायपुर-ग्रामीण में पहुंचते ही समीकरण बदला नजर आया। यहां देवपुरी में मतदान करने पहुंचे घनश्याम और उनके स्वजन ने कहा कि कांग्रेस की कर्ज माफी किसानों के लिए फायदेमंद है। मतदाताओं ने मुद्दों के आधार पर अपनी चुप्पी तो तोड़ी, मगर जब बात भ्रष्टाचार तक पहुंची तो खामोशी छा गई।

कांग्रेस को घेरने भाजपा ने बनाया था भ्रष्टाचार का मुद्दा

बता दें कि चुनाव से पहले कांग्रेस को घेरने के लिए भाजपा ने भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाया था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हों या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह या फिर अन्य कोई नेता, लगातार ईडी-आइटी की कार्रवाई और प्रदेश में शराब, कोयला, गोबर-गोठान, महादेव एप आनलाइन सट्टा घोटाले का मुद्दा उठाते रहे हैं।

भाजपा नेताओं की रैलियों में महादेव एप आनलाइन सट्टा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कथित तौर पर मिली 508 करोड़ रुपये की धनराशि को लेकर कड़े संबोधन किए गए। भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर भाजपा मतदाताओं को लगातार साधती रही है, परंतु इस चुनाव में मतदाताओं ने भ्रष्टाचार को लेकर चुप्पी साध रखी है।

कर्ज माफी को लेकर आश्वस्त है कांग्रेस

इस चुनावी वर्ष में घोषणापत्र जारी करने से पहले ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों की कर्ज माफी की घोषणा कर दी थी। बाद में उसे घोषणापत्र में शामिल किया। कांग्रेस, किसानों की कर्ज माफी से लेकर लाभार्थियों को सीधे राहत देने वाली अपनी कल्याणकारी योजनाओं के सहारे सत्ता में वापसी के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त है। बता दें कि प्रदेश के 24 लाख किसानों ने इस वर्ष 6,900 करोड़ रुपये का कर्ज लिया है।

महिला सशक्तीकरण के सहारे भाजपा

भाजपा ने सभी विवाहित महिलाओं को 12,000 रुपये सालाना देने की घोषणा अपने घोषणापत्र में की है। यही वजह है कि चुनाव में महिला मतदाताओं में इस गारंटी का जबरदस्त असर देखने को मिला। भाजपा ने इसके अलावा भी गरीब महिलाओं को 500 रुपये में गैस सिलिंडर देने की बड़ी घोषणा की है। हालांकि कांग्रेस ने भी गृह लक्ष्मी योजना शुरू करने का वादा करते हुए महिलाओं को 15,000 रुपये सालाना देने का वादा किया है, मगर यह घोषणा कांग्रेस के घोषणापत्र में शामिल नहीं होने के कारण हर महिला मतदाता तक पहुंचने में प्रभावी नहीं रही।

अन्य पार्टियों ने भी दी है गारंटी

कांग्रेस, भाजपा की तरह आम आदमी पार्टी ने 10 गारंटी में युवतियों के 18 वर्ष से अधिक होने पर हर महीने एक हजार रुपये की सम्मान राशि देने की और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ पार्टी ने बेटी के जन्म पर जोगी नोनी योजना के अंतर्गत एक लाख रुपये देने का एलान कर रखा है।

एसटी के लिए आरक्षित 28 सीटों पर 2018 के मुकाबले हुआ अधिक मतदान

छत्तीसगढ़ में आदिवासियों ने जगाई लोकतंत्र की अलख

- जिन 21 सीटों पर कम मतदान हुआ, उनमें से ज्यादातर सीटें सामान्य वर्ग की हैं।
- प्रदेश में सबसे अधिक 87.64 प्रतिशत मतदान वाली सिहावा सीट भी आदिवासी बहुल है।
- प्रदेश में लगभग 34 प्रतिशत आबादी वाले आदिवासियों की भूमिका किंग मेकर जैसी रहती है

रायपुर। आमतौर पर शहरी लोगों को अधिक जागरूक समझा जाता है, मगर प्रदेश में संपन्न हुए विधानससभा चुनाव में आदिवासियों ने लोकतंत्र की अलख जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रदेश की कुल 90 सीटों में अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षित 29 में से 28 सीटों पर 2018 के चुनाव के मुकाबले इस बार दो से पांच प्रतिशत तक मतदान बढ़ा है।

प्रदेश में सबसे अधिक 87.64 प्रतिशत मतदान वाली सिहावा सीट भी आदिवासी बहुल है। वहीं प्रदेश की जिन 21 सीटों पर कम मतदान हुआ है, उनमें ज्यादातर सामान्य सीटें हैं। माना जाता है कि प्रदेश में लगभग 34 प्रतिशत आबादी वाले आदिवासी समाज का साथ मिले बिना किसी भी पार्टी को सरकार बनाना मुश्किल है। इनकी भूमिका किंग मेकर जैसी रही है।

राजनीतिक प्रेक्षकों के अनुसार इस बार कांग्रेस-भाजपा दोनों ही दलों ने आदिवासियों को लुभाने के लिए कई आकर्षक घोषणाएं की थीं। मतदान का प्रतिशत बढ़ने का यह भी एक कारण है। वहीं राजनीतिक विश्लेषक इसे अपने चश्मे से देख रहे हैं। उनका मानना है कि अधिक मतदान के दो मायने हो सकते हैं, या तो वर्तमान सरकार की ओर से लाई गई किसी योजना को लेकर मतदाता अति उत्साहित हो गए या फिर यह प्रदेश में बदलाव का संकेत भी हो सकता है।

30 प्रतिशत सीटों पर कांग्रेस के बागी बिगाड़ सकते हैं 75 पार का समीकरण

- समीक्षा बैठकों में मिल रहे फीडबैक से पार्टी परेशान, लगातार कार्रवाई भी कर रही
- कांग्रेस में भारतीय जनता पार्टी से अधिक बागी
- प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा का दावा- छत्तीसगढ़ में बनेगी कांग्रेस की सरकार

रायपुर। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और भाजपा के बागी और भितरघाती सीटों का समीकरण बिगाड़ सकते हैं। दोनों पार्टियों की समीक्षा बैठकों में यह फीडबैक मिला है। इसमें सबसे अधिक नुकसान कांग्रेस को हो रहा है। इससे कांग्रेसियों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। बीस बागियों में 12 कांग्रेस और आठ भाजपा के हैं। इनके अलावा 15 सीटों पर कांग्रेस को भितरघातियों से भी नुकसान पहुंचने की आशंका है। इस तरह कांग्रेस को 27 सीटों पर नुकसान हो रहा है, जिससे कांग्रेस का 75 पार का दावा सिमटता नजर आ रहा है। कांग्रेस और भाजपा के बीच अब बराबरी की टक्कर दिख रही है। तीन दिसंबर को परिणाम आने के बाद ही पता चल पाएगा कि बागियों और भितरघातियों ने किस पार्टी को कितना नुकसान पहुंचाया है।

टिकट की पहली सूची आने के बाद से ही कांग्रेस बागियों और भितरघातियों से परेशान रही। पार्टी ने ऐसे लगभग 50 नेताओं पर निष्कासन, निलंबन समेत अन्य कार्रवाई भी की है। वहीं आधा दर्जन से अधिक नेताओं को नोटिस भेजकर स्पष्टीकरण भी मांगा है। हालांकि कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने दावा किया है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। अच्छा फीडबैक मिला है। 75 पार सीटों के दावों पर उन्होंने कहा कि अभी इसमें ओवर कान्फिडेंस नहीं होना चाहिए।

कांग्रेस के बागी

जशपुर विधानसभा सीट से प्रदीप खेस कांग्रेस प्रत्याशी विनय भगत के खिलाफ, सक्ती विधानसभा अनुभव तिवारी प्रत्याशी डा. चरणदास महंत के खिलाफ, जैजैपुर से टेकचंद्र चंद्रा प्रत्याशी बालेश्वर साहू के खिलाफ, पामगढ़ से गोरेलाल बर्मन शेषराज हरबंश के खिलाफ, पाली-तानाखार से छत्रपाल सिंह दुलेश्वरी सिदार के खिलाफ, लोरमी से सागर सिंह बैस थानेश्वर साहू के खिलाफ, मुंगेली से रूपलाल कोसरे संजीत बनर्जी के खिलाफ, सरायपाली से विधायक किस्मतलाल नंद चातूरी नंद के खिलाफ, रायपुर उत्तर से अजीत कुकरेजा कुलदीप जुनेजा के खिलाफ, धमतरी से लोकेश्वरी साहू ओंकार साहू के खिलाफ, बालोद से मीना साहू संगीता सिन्हा के खिलाफ और कसडोल से गोरेलाल साहू संदीप साहू के खिलाफ चुनाव लड़ा है।

बिलासपुर महापौर निलंबित, अन्य पर भी कार्रवाई

कांग्रेस ने बिलासपुर के महापौर रामशरण यादव को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। उन पर पार्टी संगठन के खिलाफ अनर्गल वार्तालाप करने का आरोप है। वहीं जिन बागियों को छह साल के लिए निलंबित किया है, उनमें जशपुर से प्रदीप खेस, जांजगीर से गुड्डू महराज, सरायपाली किस्मतलाल नंद, पामगढ़ से गोरेलाल वर्मन, रायगढ़ से शंकर अग्रवाल, मुंगेली से रूपलाल कोसरे, भाटापारा से मनोहर साहू, संजारी बालोद से मीना साहू, पाली तानाखार से छत्रपाल सिंह कंवर, कवर्धा से योगेश्वर राज सिंह, सामरी से प्रभातबेला मरकाम, लैलूंगा से महेंद्र सिदार, वैशाली नगर से अजहर अली, अंतागढ़ से अनूप नाग, कांति नाग, दंतेवाड़ा से अमूलकर नाग, महासमुंद से विश्वजीत बेहरा और बिलासपुर से प्रेमचंद्र जायसी शामिल हैं।

सीट बढ़ाने के लिए पार्टियों ने लिया बागियों का सहारा

दर्जनभर नेताओं ने मुकाबले को बनाया त्रिकोणीय

रायपुर। विधानसभा चुनाव में इस बार दलबदलू नेताओं की भी काफी दखल रही। भाजपा, कांग्रेस और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे (जकांछ) ने लगभग दर्जनभर ऐसे नेताओं को मैदान में उतारा था, जो अन्य दोनों पार्टियों में से किसी एक से अलग हो गए थे। यानी बागियों को शरण देने के बाद इन पार्टियों ने उन्हें पूरी तवज्जो दी। ऐसा इन पार्टियों ने इस उम्मीद के साथ किया कि उनकी जीत का आंकड़ा बढ़ जाएगा। अब यह तो तीन दिसंबर को चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चल पाएगा कि इस रणनीति का किस पार्टी को कितना फायदा या नुकसान हुआ।

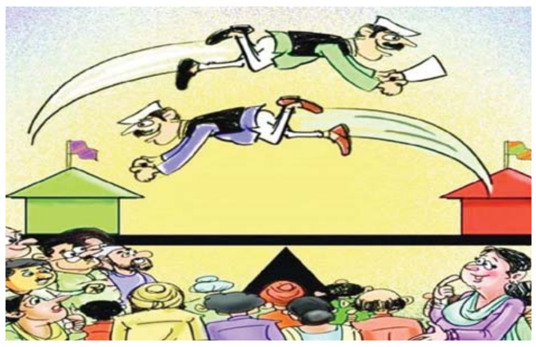

वैसे देखा जाए तो प्रदेश की कुल 90 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस और भाजपा के बीच ही असली मुकाबला है। कुछ सीटों पर जकांछ, बहुजन समाज पार्टी (बसपा), आम आदमी पार्टी (आप) और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी (गोगपा) की भूमिका मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की ही रही। कांग्रेस और भाजपा दोनों ने क्षेत्रीय जाति समीकरणों और जनता के समर्थन को ध्यान में रखते हुए ही एक दर्जन से अधिक दलबदलुओं को मैदान में उतारा।

सभी पार्टियों में दलबदलुओं की दखल

कांग्रेस ने जांजगीर-चांपा निर्वाचन क्षेत्र से व्यास कश्यप को मैदान में उतारा, जिन्होंने 2018 का विधानसभा चुनाव बसपा के टिकट पर लड़ा था और उससे पहले वह सक्रिय रूप से भाजपा का हिस्सा थे। इसी तरह गुरु खुशवंत सिंह को आरंग निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा ने उतारा, जो मौजूदा कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता शिव डहरिया के खिलाफ चुनाव लड़े। वह पहले कांग्रेस में थे। अनुभवी कांग्रेस नेता धरमजीत सिंह लोरमी सीट से 2018 के चुनाव में जकांछ के विधायक चुने गए थे। वह हाल ही में भाजपा में शामिल हुए और पार्टी ने उन्हें तखतपुर से टिकट दिया। जकांछ ने मस्तूरी सीट से भाजपा की बागी चांदनी भारद्वाज को मैदान में उतारा।

दलबदलू किसी पार्टी से ही जीतते रहे

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि छत्तीसगढ़ में जिन नेताओं और विधायकों ने पार्टियां बदली हैं, वे लंबे समय से राजनीति में नहीं हैं। अगर किसी अन्य पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया है तो वे जीतने में सफल रहे हैं लेकिन अगर उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा है तो उनका राजनीतिक भविष्य भी खतरे में है क्योंकि राज्य की जनता दलबदलू नेताओं पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती। हालांकि, इस चुनाव में सभी पार्टियों ने दलबदलुओं को प्रत्याशी बनाया है।

दलबदल करने वालों का रिकार्ड ठीक नहीं

प्रदेश में दलबदल करने वाले नेताओं का रिकार्ड कभी अच्छा नहीं रहा। एक-दो मामलों को छोड़ दें तो दलबदल करने वाले नेताओं को न नए दल में कार्यकर्ताओं का समर्थन हासिल होता है, न जनता सर माथे पर बिठाती है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद सबसे बड़ा दलबदल पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के कार्यकाल में हुआ था। जोगी ने विपक्ष भाजपा के 12 विधायकों को तोड़ लिया था। हालांकि तब जो दलबदल कर सत्तापक्ष के साथ गए थे, उनमें से अधिकांश चुनाव हार गए और अब राजनीतिक हाशिए पर हैं।

मतदान सामग्री वितरण के समय शराब पीकर आने वाले प्रधान पाठक और शिक्षक निलंबित

महासमुंद। निर्वाचन कार्य के दौरान शराब पीने की पुष्टि होने पर मतदान दल अधिकारी क्रमांक 1 कार्तिकेश्वर भोई प्रधान पाठक शासकीय प्राथमिक शाला सुखापाली एवं मतदान अधिकारी क्रमांक 2 थानेश्वर प्रसाद मार्कण्डेय शिक्षक ई (एलबी) शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला मानपुर को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रभात मलिक ने निलंबित कर दिया है।

विधानसभा निर्वाचन 2023 अंतर्गत 16 नवंबर को कृषि उपज मंडी पिटियाझर महासमुंद में मतदान सामग्री वितरण के दौरान दोनों अधिकारियों द्वारा लापरवाही पूर्वक कार्य करने की सूचना मिलने पर डॉक्टरी मुलाहिजा कराया गया। जिसमें दोनों को शराब का सेवन किया जाना पाया गया।

छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय नेताओं ने 35 दिनों में की 100 से अधिक सभाएं

खूब गरजे मोदी-योगी, राहुल-खरगे

रायपुर। इस बार का विधानसभा चुनाव प्रदेश के लिए यादगार बन गया। राज्य बनने के बाद अब तक हुए चुनावों में इस बार रिकार्ड सभाएं आयोजित की गईं, जिनमें प्रधानमंत्री से लेकर कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों के कई केंद्रीय नेता शामिल थे। इस तरह लगभग 35 दिनों में 100 से अधिक सभाओं को एक करोड़ से अधिक लोगों ने सुना। चुनाव की घोषणा होते ही स्टार प्रचारकों ने मोर्चा संभाल लिया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वयं छह सभाएं की। गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी

आदित्यनाथ, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे भी सभाओं में खूब गरजे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महासमुंद, मुंगेली, कांकेर और दुर्ग में बड़ी चुनावी सभाएं कीं। गृह मंत्री अमित शाह ने राजनांदगांव, चंद्रपुर, बिलासपुर, बस्तर, जगदलपुर, कोंडागांव, कांकेर, कवर्धा, जशपुर आदि सीटों में गरजे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने अंतागढ़, डोंगरगांव, पंडरिया, कवर्धा, बिरगांव में सभा के साथ रोड-शो भी किया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अंबिकापुर, बलौदाबाजार, बेमेतरा, जगदलपुर और खरसिया में सभा को संबोधित किया। प्रियंका गांधी 15 नवंबर को रायपुर में रोड-शो में शामिल हुईं। इसके अलावा उन्होंने कुरुद, बिलासपुर, बालोद और खैरागढ़ में रैलियों को संबोधित किया। खरगे ने भी कई सभाएं कीं।

इन्होंने भी फूंकी जान

भाजपा के स्टार प्रचारकों में शामिल असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा सहित केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, स्मृति ईरानी सहित कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ताओं और पूर्व केंद्रीय नेताओं ने भी सभा में मोर्चा संभाला। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस की छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी सैलजा ने सरकार के पांच सालों के काम को बताने के लिए ताबड़तोड़ रैलियां की।

कांग्रेस का दावा 75 से ज्यादा जीतेंगे सीट, भाजपा बोली- बहुमत से बनाएंगे सरकार

रायपुर। छत्तीसगढ़ में सभी 90 विधानसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। गली-शहर के हर चौक-चौराहे, पान ठेले, गुमचे, होटल-रेस्टोरेंट में खामोश मतदाता अपनी-अपनी चुप्पी तोड़ रहे हैं। कोई सरकार बनाते हुए नजर आ रहा है तो कोई सरकार गिरने का दावा कर रहा है। इस बीच कांग्रेस-भाजपा दोनों की राजनीतिक दलों ने अपनी-अपनी सरकार बनाने का दावा किया है। बहरहाल मतदाताओं ने ईवीएम में किस प्रत्याशी के भाग्य को चमकाया है यह तो आने वाले तीन दिसंबर की मतगणना में ही पता चल पाएगा।

कांग्रेस का दावा 75 से ज्यादा जीतेंगे सीट

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद दीपक बैज ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा इस चुनाव को प्रभावित करने के लिये छत्तीसगढ़ की शांत फिजा को खराब करने के षडयंत्र रचा था लेकिन असफल रहे। प्रदेश की जागरूक मतदाता भाजपा के बहकावे में नहीं आई। छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस सरकार के काम एवं कांग्रेस के घोषणा पत्र पर भरोसा किया। कांग्रेस 75 से अधिक सीट जीतकर पुनः सरकार बनाने जा रही है।

उन्होंने कहा कि प्रथम और दूसरे चरण के मतदान में किसान, माता, बहने, युवा, श्रमिक व्यापारियों का रूझान कांग्रेस के प्रति मिला। कांग्रेस की सरकार बनते ही जनता से किये सभी वादों पर काम शुरू होगा। मोदी की गारंटी और भाजपा के झूठे एवं मनगढ़त आरोप को जनता ने खारिज कर दिया है।

भाजपा का दावा, बहुमत से बनाएंगे सरकार

इधर, भाजपा का भी दावा है कि वह बहुमत के साथ सरकार बना रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि प्रदेश की जनता कांग्रेस सरकार की वादाखिलाफी के साथ साथ अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, छलावा से बेहद रुष्ट है और जनता ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ अपने आक्रोश को अपने मताधिकार के जरिए व्यक्त किया है। अब यह आईने की तरह साफ हो गया है कि परिवर्तन की आंधी में कांग्रेस और उसकी भूपेश सरकार का छत्तीसगढ़ में सूपड़ा साफ होने जा रहा है।

पूर्व मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह ने कहा कि मतदान के प्रति जनता, खासकर महिलाओं और युवाओं के उत्साह भूपेश सरकार की बिदाई का फरमान है। भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व राज्यसभा सासंद डा. सरोज पाण्डेय ने कहा कि मतदान के प्रति प्रदेश के मतदाताओं के उत्साह से भाजपा का यह विश्वास दृढ़तर हो गया है कि पहले चरण की तरह दूसरे चरण का मतदान भी भाजपा के लिए अनुकूल परिणाम लेकर आएगा।

विधायक प्रतिनिधि कमल के साथ ओपी चौधरी की नोकझोंक

- ग्रामीणों ने लगाए कांग्रेस मुर्दाबाद के नारे
- हॉट सीट रायगढ़ खरसिया में छिटपुट वाद विवाद
- एजेंट नहीं मिला तो बैठा दिया बच्चे को

रायगढ़। मतदान के दौरान बीजेपी प्रत्याशी ओपी चौधरी पंचधार के बूथ पर जाकर मतदाताओं से वोट की अपील कर रहे थे। विधायक प्रतिनिधि कमल प्रधान तथा ग्रामीणों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई । जिसके बाद कमल प्रधान और ओपी चौधरी के मध्य तीखी बहस हुई। कमल प्रधान का कहना था कि कोई भी प्रत्याशी मतदाता को बूथ के अंदर वोट की अपील नहीं कर सकता।

ओपी चौधरी का कहना था कि वो केवल वोटरों से मिल रहे हैं जबकि ग्रामीणों का कहना था कि वो बूथ के अंदर वोट मांग रहे थे। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच गाली गलौज भी हुआ।उसके बाद नगर पंचायत सरिया के अध्यक्ष और सुखदेव दीवान के साथ कमल प्रधान की बहस हुई। ततपश्चात कांग्रेस नेता विधायक प्रकाश नायक के भाई कैलाश नायक और कई कांग्रेस कार्यकर्ता पोलिंग बूथ पर पहुंच गए जिसके बाद दोनो पक्षों द्वारा जोरदार बहस हुआ। जिसकी सूचना प्राप्त होने के बाद पुलिस बल पहुंचकर दोनों पक्षों को शांत कराया। वही इस दौरान कांग्रेस मुर्दाबाद के नारे भी ग्रामीणो ने लगाए।

शहर में सभी पोलिंग बूथ के बाहर मतदाताओं का नाम से लेकर अन्य सुविधाएं के लिए राजनीतिक दलों ने टेंट लगाकर मदद को बैठे थे। वही कई मतदान केंद्र में निर्दलीय उम्मीदवार को सहयोग करने के लिए एजेंट नही मिला। राजनीतिक दलों को बच्चों को मतदान केंद्र के बाहर सहायता केंद्र के टेंट पर बैठाना पड़ गया।

हॉट सीट रायगढ़ खरसिया में छिटपुट वाद विवाद

हॉट सीट रायगढ़ खरसिया विधानसभा में रायगढ़ के बाद सबसे अधिक विवाद होने की सूचना अलग अलग मतदान केंद्र से मिली है। बताया जा रहा है कि शहर सहित कुछ ग्रामीण अंचल में छिटपुट विवाद हुआ है।

छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार, रायपुर उत्तर में महिलाओं ने संभाली मतदान की जिम्मेदारी

पीठासीन से लेकर मतदान अधिकारी तक सभी महिलाएं ही थीं

रायपुर ।रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के सभी 201 मतदान केंद्रों में इस बार सिर्फ महिलाओं ने मतदान कराने की जिम्मेदारी संभाली। प्रदेश में पहली बार किसी विधानसभा क्षेत्र का जिम्मा पूरी तरह महिलाओं को मिला। यहां पीठासीन से लेकर मतदान अधिकारी तक सभी महिलाएं ही थीं। 804 महिलाएं प्रत्यक्ष जबकि 200 महिलाएं विशेष परिस्थितियों के लिए तैनात थीं। पर्यवेक्षक भी महिला आइएएस विमला आर थीं। प्रदेश की मुख्य चुनाव अधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले भी महिला हैं।

कलेक्टर डा. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने कहा, निर्वाचन प्रक्रिया शुरू होते ही हमें यह विचार आया कि क्यों न जिले की एक विधानसभा में

निर्वाचन का पूरा दायित्व महिलाओं को सौंपा जाए। सभी ने इसे सराहा। महिलाएं भी हमारे भरोसे पर खरी उतरीं।

रायपुर की उत्तर विधानसभा सीट पर इस बार त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है। दरअसल, कांग्रेस ने संसदीय सचिव कुलदीप जुनेजा को चुनावी मैदान में उतारा है तो वहीं कांग्रेस के ही बागी अजीत कुकरेजा निर्दलीय चुनाव लड़ने से इस सीट पर मुकाबला रोचक हो गया है।

संपादकीय

महंगी है दाल-रोटी

हाल ही में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, मूल मुद्रास्फीति, थोक मूल्य सूचकांक की दरें घोषित की गई हैं। औसतन मुद्रास्फीति की दर लक्षित दर से कम है, लिहाजा भारत सरकार गाल बजा सकती है कि उसने महंगाई को नियंत्रित रखा है, लेकिन यथार्थ कुछ और ही है। सामान्य और आसान शब्दों में कहें, तो आम आदमी के लिए 'दाल-रोटी की मुद्रास्फीति' अब भी ज्यादा है। महंगाई अब भी काफी ज्यादा है। बेशक अर्थशास्त्र की भाषा में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक स्पष्ट करता है कि अक्तूबर में सालाना खुदरा मुद्रास्फीति 4.87 फीसदी है। यह जुलाई में 7.44 फीसदी थी, जिससे लगातार कम होती गई है। मूल मुद्रास्फीति (कोर इंफ्लेशन) 4.28 फीसदी बताई गई है, लेकिन उसमें खाद्य और ईंधन की बढ़ती कीमतें शामिल नहीं हैं। बताया गया है कि यह दर 43 माह में सबसे कम रही है। थोक मूल्य सूचकांक शून्य से 0.52 फीसदी नीचे रहा है। दावा किया जा रहा है कि अक्तूबर में खाद्य पदार्थों की महंगाई घटकर 2.53 फीसदी पर आ गई। सितंबर माह में यह महंगाई 3.35 फीसदी थी। थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति अप्रैल से लगातार शून्य से नीचे रही है, उस लिहाज से महंगाई के मोर्चे पर राहत की खबर लगातार मिल रही है, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास इसे 'अति संवेदनशील स्थिति' मानते हैं। दरअसल खाद्य वस्तुओं की कीमतें ही बुनियादी समस्या रही हैं और वे ही महंगाई को परिभाषित करती हैं। 2024 के आम चुनाव से पहले खाद्य मुद्रास्फीति से जुड़े कुछ कठिन और चिपचिपे अवयव मोदी सरकार और आरबीआई को चिंतित कर रहे हैं। दरअसल दाल-रोटी अर्थात अनाज और दालों की खुदरा मुद्रास्फीति करीब 10.65 फीसदी है।

बीते 14 महीनों, सितंबर 2022, से ही यह दहाई में रही है। दालें भी बीते पांच महीनों से दहाई की दर में महंगी रही हैं। इनकी मौजूदा मुद्रास्फीति 18.79 फीसदी है, जो अगस्त, 2016 से उच्चतम रही है। इसका मानसून से प्रत्यक्ष संबंध हो सकता है। खाद्य मुद्रास्फीति का 6.61 फीसदी पर आकलन करें, तो सामान्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से अधिक है। खाद्य के साथ-साथ सब्जियां भी हैं, जिनकी मौसमी आपूर्ति की कमी बार-बार आम नागरिक को परेशान करती है। नतीजतन जुलाई-अगस्त में टमाटर 200 रुपए किलो तक बिका और आजकल प्याज 70-80 रुपए किलो बेचा जा रहा है।

चुनाव सरकार नहीं, देश को गढ़ने का होना चाहिए

अमन नम्र

मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम जैसे पांच राज्यों में चुनाव प्रचार जोरों पर है। सत्ता, विपक्ष और सत्ता में आने को लालायित नाना प्रकार की पार्टियां अपने लोकलुभावन वादों से जनता को बहलाने में जुटी हैं। जनता को विकल्प भी इन्हीं में से चुनना है। जल्द ही नई सरकारें चुनी जाएंगी जो अगले पांच सालों तक इनके विकास की बागडोर थामेंगी। इसके तीन-चार महीने बाद लोकसभा चुनाव होंगे और देश की सरकार बनेगी जो भविष्य की दशा और दिशा तय करेगी। सवाल यह है कि क्या यह दशा और दिशा बीते सात दशकों से जारी विकास की मौजूदा अवधारणा से अलग या बेहतर होगी ? विषय थोड़ा गंभीर है, पर मौजूं है और हमारे आपके ही नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पर विचार करना जरूरी है।

पहले हाल की दो खबरों की सुर्खियां पढ़िए। पहली,- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगले पांच साल तक देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन की योजना जारी रहेगी। दूसरी- दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। अगर पहली सुर्खी की बात करें तो यह तथ्य हमें चुल्लू भर पानी में डूबने पर मजबूर कर देगा कि 76 साल पहले जब देश को आजादी मिली थी, उस समय की आबादी (34 करोड़) की तुलना में आज मुफ्त राशन पाने वाले गरीबों की संख्या दोगुना से ज्यादा है। यह तमाम 'पंचवर्षीय, 7 वर्षीय' योजना आयोग, नीति आयोग या कांग्रेस, भाजपा, जनता पार्टी या यूपीए, एनडीए शासित सरकारों के विकास का नतीजा है।

इसी विकास का एक नतीजा दूसरी सुर्खी भी है कि हमारे देश की राजधानी दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में टॉप पर है। क्या ऐसा नहीं लग रहा कि हम विकास के नाम पर 76 साल पहले जिस गलत दिशा में मुड़ गए थे, उसी दिशा में अब इतने आगे पहुंच चुके हैं कि विनाश को ही अब हमने विकास समझ लिया है।

इस बात को हम तीन तरह से देख, समझ सकते हैं। आजादी से पहले और आजादी की लड़ाई के दौरान भविष्य के किस भारत की कल्पना की गई थी। मजबूरी में हमने किस तरह का भारत बनाना शुरू किया और जो भारत आज बना, उसका भविष्य क्या है। यह कम-से-कम उस भारत की दिशा में जा रहा देश तो कतई नहीं है जिसकी कल्पना और सोच महात्मा गांधी ने की थी। हिंद स्वराज का सपना देखने वाले गांधी कहते थे कि हमारी पहली प्राथमिकता विदेशी राज्य को हटाना है और हिंद स्वराज के लिए अभी जनता तैयार नहीं हो पाई है इसलिए सारी ताकत 'संसदीय स्वराज' दिलाने में लगा देनी है। हमारे हुक्मरानों ने 'संसदीय स्वराज' वाले गांधी को तो याद रखा, पर यह भूल गए कि यह केवल तात्कालिक व्यवस्था थी। गांधी का असली सपना 'संसदीय स्वराज' नहीं, 'हिंद स्वराज' का था। आज हम गांवों को खत्म कर शहरों के दायरे बढ़ाते जा रहे हैं पर गांधी इसके पूरी तरह खिलाफ थे। शहरों के बढ़ते प्रभुत्व के खिलाफ आवाज उठाने वाले गांधी ने गांवों के संरक्षण की बात कही थी।

यहां यह सवाल पूछा जा सकता है कि अब गांधी कितने प्रासंगिक हैं ? जवाब है कि अगर गांधी और उनके विचार प्रासंगिक नहीं हैं तो सरकार आधिकारिक तौर पर उन्हें हटा क्यों नहीं देती। दरअसल गांधी कभी किसी व्यक्ति का नाम नहीं रहा। वह तो आजादी के लिए देश के कोने-कोने में घूमकर लोगों को जागृत करने वाली ऐसी विचारधारा थी जो उस वक्त मिट्टी में ही घुलमिल गई थी और आज भी देश की मिट्टी, हवा, पानी और इसकी आत्मा का अहम हिस्सा है। कम से कम आज सात दशक बाद हम थोड़ा सा ठहर कर यह विचार तो कर ही सकते हैं कि अगर देश बनाने का गांधी का ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विचार सही नहीं था तो क्या बड़े बांध और बड़े उद्योगों को 'आधुनिक भारत के मंदिर' कहने वाले नेहरू का मॉडल सही था ?

इसे जानने का सबसे आसान तरीका यह है कि हम देखें कि आजादी के समय किस तरह के भारत को बनाने के विकल्प पर विचार किया गया था। गांधी की सोच थी कि भविष्य के समाज का धारण और पोषण यानी समाज का विकास धर्म, बंधुत्व और परिवार भावना से होना चाहिए, नहीं तो देश चलाने के लिए 'शैतानी ताकतों' का सहारा लेना पड़ेगा। उसमें जबरदस्ती होगी, आतंक होगा और उसके समर्थन के लिए आपको राज्य, लोकतंत्र, चुनाव, समाजवाद जैसी कोई-न-कोई प्रतिमा खड़ी करनी होगी। गांधी ने करीब सौ साल पहले ही आज की हालत की कल्पना कर ली थी। तब उन्होंने समाज गढ़ने के दो विकल्प सुझाए थे। एक सभ्य समाज, जो स्वतंत्र व्यक्तियों का बना हुआ हो और जिसके धारण, पोषण के लिए कानून, व्यवस्था, राजतंत्र का ढांचा, संविधान आदि हो। जिसका दिन-प्रतिदिन विस्तार होता जाए। दूसरा- पारिवारिक समाज जिसका धारण पोषण पारिवारिक भावना से हो।

त्योहारों की बेला में महंगाई का सितम

अनुज आचार्य

आशा है कि केंद्र एवं राज्य सरकारें उत्पादों का निर्माण करने वाले निर्माताओं और खुदरा कारोबारियों से उपभोक्ताओं को बेरहमी से लुटने से बचाने के लिए एमआरपी यानी अधिकतम खुदरा मूल्य तय करने के लिए एक तंत्र विकसित करेंगी और सख्ती से इस नीति के अंतर्गत नियम कानूनों का अनुपालन भी करवाया जाएगा, ताकि ग्राहकों को उचित मूल्य पर सामग्री/वस्तुएं मिलती रहें। अंततः सवाल उठता है कि क्या अफसरशाही के पास इस लूटपाट को अंजाम देने वाले जमाखोरों के खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई करने का जीवट है?

आजकल भारत में प्याज की बढ़ती कीमतों ने गृहणियों की आंखों में आंसू ला रखे हैं। इससे पहले टमाटर लाल पीला हो रखा था। भारत में कुल प्याज उत्पादन का लगभग 30 फीसदी महाराष्ट्र राज्य में पैदा होता है। महाराष्ट्र में भी सबसे ज्यादा प्याज पैदा करने वाले तीन जिले नासिक, अहमदनगर और पुणे हैं। इस राज्य का लाल प्याज अपने स्वाद और तेज गंध के लिए प्रसिद्ध है। त्योहारी सीजन से पहले टमाटर के दामों में राहत मिले अभी कुछ ही दिन हुए थे कि अब प्याज की कीमतें भी लगातार बढ़ रही हैं। पिछले 20 दिनों में प्याज के दामों में जबरदस्त इजाफा हुआ है और यह मूल्य वृद्धि लोगों की जेब पर भारी पड़ रही है। प्याज की बढ़ती हुई कीमतों पर सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि बढ़ती कीमतों के पीछे बाजार में प्याज की कमी है और जब प्याज की पर्याप्त आपूर्ति बढ़ेगी तो कीमतें नियंत्रण में आ जाएंगी। लेकिन फिलहाल तो आशंका है कि प्याज की कीमतें 100 रुपए प्रति किलो तक पहुंच सकती हैं। तब तक व्यापारियों के वारे न्यारे हो चुके होंगे और आम आदमी की जेबें खूब ढीली हो गई होंगी। कहीं कहीं सरकार द्वारा 25 रुपए किलो की दर से प्याज उपलब्ध करवाया जा रहा है, लेकिन इससे पूरे देश-प्रदेश के नागरिकों को तो राहत नहीं मिल रही है। इस बात से भी सभी भली-भांति परिचित ही हैं कि आम आदमी तक खाद्य सामग्री पहुंचने से पहले दलालों, बिचौलियों और आढ़तियों की जेबें गर्म हो चुकी होती हैं, जबकि किसानों को कभी भी उनके उत्पादों के सही दाम नहीं मिलते हैं।

उल्टे खून पसीना बहाने वाले इन किसानों की कमर कर्ज की मार से झुकी रहती है। रिटेल बाजार में खाद्य पदार्थों और सब्जियों के दाम चाहे कितने भी क्यों न बढ़ जाएं, लेकिन किसान वर्ग को इसका फायदा कभी भी नहीं मिलता है। इसके विपरीत जमाखोरों-स्टोरियों द्वारा जमकर खाद्य वस्तुओं की जमाखोरी की जाती है और बाजार में वस्तुओं का कृत्रिम अभाव पैदा कर महंगाई को बढ़ाकर चोखा मुनाफा कमाया जाता है। हिमाचल प्रदेश के सरकारी आंकड़ों में पिछले कुछ दशकों से घरेलू सब्जी उत्पादन एवं अनाज की पैदावार में बढ़ोतरी दर्ज की गई है तो वहीं दूसरी तरफ बंदरों के उत्पाद और बेसहारा पशुओं की टोलियों के चलते अधिकतर जगहों पर कृषि कार्यों में आ रही परेशानियों के चर्चे भी अक्सर सुनने को मिलते रहते हैं। जो छोटे किसान अपनी मेहनत के बलबूते थोड़ा बहुत अन्न एवं सब्जी उत्पादन कर भी रहे हैं तो उनकी सबसे बड़ी समस्या अपनी वस्तुओं की बिक्री को लेकर है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रशासन को यह पता ही नहीं है कि बाजारों में सब्जियों के दामों और अन्य खाद्य वस्तुओं का क्या हाल है और अधिकारी वर्ग अपनी कुर्सियों तक सीमित होकर रह गए हैं। आज से 30-35 वर्ष पूर्व जब कभी भी महंगाई का जिन्न अपना सिर उठाता था तो विपक्षी दलों द्वारा जरूर धरना प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन की खबरें देखने सुनने को मिलती थीं। लेकिन अब जैसे राजनीतिक दलों को आम जनता को होने वाली परेशानियों से कोई लेना देना ही नहीं है। हिमाचल प्रदेश में नवम्बर महीने की शुरुआत तक सब्जियों की पैदावार बढने के साथ ही इनके दाम नीचे आ जाते थे, लेकिन इस बार ऐसा होता दिखाई नहीं पड़ रहा है। बाजार में टमाटर 40, तो हरा मटर 140 रुपए पार बिक रहा है। अदरक 160 रुपए तो बाकी सब्जियों के मूल्य भी लगभग 60 रुपए पार ही हैं और खुदरा दुकानदार मोटा मुनाफा कूटने में जुटे हुए हैं।

खरीदी की रफ्तार बढ़ने से पहले केंद्रों से धान उठाव शुरू

किसानों ने इस बार नए सरकार गठन के इंतजार में धान बिक्री से दूरी बना रखी है

कोरबा । जिले के उपार्जन केंद्रो में धान खरीदी को लेकर भले ही प्रगति न आई हो लेकिन विपणन विभाग ने उठाव शुरू कर दिया है। शासन ने प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी का निर्णय लिया है। उपार्जन केंद्रों में धान रखने के लिए जगह कम पड़ने की आशंका को देखते हुए अभी से उठाव किया जाने लगा है। खरीदी कार्य शुरू होने के 20 दिन के भीतर 2,760 क्विंटल धान की खरीदी हो चुकी है।

धान खरीदी में इस बार विधानसभा चुनाव के दौरान राजनैतिक दलों के घोषणा पत्रों का प्रभाव देखा जा रहा है। बड़े राजनैतिक दलों ने अपनी जीत सुनिश्चत करने के लिए किसानों को रिझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। कर्ज माफ, 20 से 21 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदी, एक मुश्त राशि का भुगतान, दो साल का बोनस, प्रति क्विंटल 3,100 रूपये भुगतान जैसे वायदों के बीच अब किसान सरकार गठन का इंतजार कर रहे हैं। धान उपार्जन को सुविधाजनक बनाने के लिए शासन ने इस बार भी पांच नए केंद्रों को स्वीकृति दी है। आम तौर पर धान उपार्जन शुरू होने के पखवाड़े भर बाद खरीदी में तेजी आ जाती थी लेकिन इस बार नए सरकार गठन के इंतजार में धान बिक्री से दूरी बना रखी है।

धान बेचने के लिए वे ही किसान आ रहे हैं जिन्होने बिना ऋण लिए खेती की है। ऋणी किसानों को कर्जा माफी का इंतजार है। बताना होगा कि इस वर्ष खेती में मानसून का साथ होने की वजह बंफर फसल की संभावना व्यक्त की जा रही है। तीन दिसंबर के बाद धान खरीदी में तेजी आएगी। धान खरीदी के दौरान उपार्जन केंद्रों धान रखने के लिए जगह कम पडने की संभावना को देखते हुए जिला विपणन विभाग ने अभी से उठाव शुरू कर दी है। धान खरीदी में बिचौलियों सक्रियता को रोकने के लिए इस बार बायोमिट्रिक डिवाइस से धान खरीदी की जा रही है। रकबा सत्यापन के बाद भी किसानों के धान की खरीदी होगी। सोमवार को 880 क्विंटल धान का उठाव किया गया। 65 में 41 केंद्र अभी भी बोहनी से दूर हैं।

मोटा, पतला सरना का अलग लाट

धान को ड्रेनेज में रखना अनिवार्य होगा। इसके अलावा प्रत्येक किस्म के धान को अलग अलग लाट में रखने की हिदायत दी गई है। इससे पहले जिस तरह से धान के लाट को बेतरतीब रखे जाने से उठाव के समय अतिरिक्त समय लगता था। लाट में धान रखने से उठाव में सुविधा होगी। खरीफ वर्ष 2023-24 में 25 लाख क्विंटल धान की खरीदी की जानी है। शासन के

निर्देशानुसार प्रत्येक बीज की सुरक्षा की जिम्मेदारी समितियों की रहेगी।

किसानों से नहीं ले सकेंगे काम

धान की सुरक्षा, हमाल से काम करवाने व किसानों की प्रत्येक सुविधा के लिए शासन की ओर प्रत्येक क्विंटल के दर से 12 रूपये सुरक्षा राशि जारी की जाएगी। उक्त राशि में से पिछली धान खरीदी के दर से तीन रूपये जारी किया गया है। इस आशय से किसानों से धान पलटी हमाल से ही कराया जाएगा। समिति प्रबंधक धान की खरीदी के लिए के लिए किसानों से काम नहीं ले सकेंगे। उपार्जन केंद्र में धान की कीमत संबंधित फ्लैक्स, विद्युतीकरण, पेयजल सुविधा आदि सुनिश्चत करने के लिए प्रबंधकों से कहा गया है। अव्यवस्था की स्थिति में किसानों द्वारा शिकायत किए जाने पर प्रशासन स्तर पर कार्रवाई की जाएगी।

केंद्र बढ़ने से परिवहन खर्च हुआ कम

जिले में इस वर्ष पांच नए उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। जिनमें चिर्रा, कुदमुरा, नवापारा, बक्साही के नवापारा शामिल है। दो वर्ष पहले जिले के 49 उपार्जन केंद्रों में खरीदी हो रही थी। 16 नए केंद्रों के अस्तित्व में आने से अब धान खरीदी की संख्या 65 हो गई है। नए केंद्रों के खुलने से किसानों को लंबी दूरी तय करने की समस्या से मुक्ति मिल रही है, साथ ही परिवहन खर्च कम हो गया है। धान की सुरक्षा के लिए शेड, चबूतरा व गोदाम निर्माण की प्रक्रिया अभी भी शुरू नहीं की गई है। उपार्जन केंद्रों में धान बिक्री के लिए पहुंचे किसानों के लिए बैठक की भी सुविधा नहीं है।

62 लाख बारदानों की जरूरत, 45 लाख उपलब्ध

नए खरीफ वर्ष में धान 25 लाख क्विंटल धान खरीदी का लक्ष्य निर्धारित है। उपार्जित धान को रखने के लिए 62 लाख बारदानों की आवश्यकता होगी। बीते वर्ष की तरह इस साल भी नए और पुराने बारदानों में खरीदी होगी। विपणन विभाग 34.50 लाख नए बारदाने उपलब्ध हैं। अगस्त माह से अब तक 11 लाख पुराने बारदानों का संग्रहण किया जा चुका है। वर्तमान में कुल उपलब्ध बारदाने 45.50 लाख हैं। अभी भी आवश्यकता की तुलना में 16.50 लाख बारदाने कम हैं। दो साल पुराने बारदानों में उपयोगी ढूंढना मुश्किल हो गया है। जीर्ण बारदानों में भराई से धान बिखरने की आशंका बनी है।

5,356 नए किसानों ने कराया है पंजीयन

मिलिंग कार्य के लिए के लिए मिलर्स से अनुबंध की प्रक्रिया जिला खाद्य विभाग ने शुरू कर दी है। बीते वर्ष उपार्जित धान की मिलिंग जिले के 87 मिलर्स ने की थी। नए खरीफ वर्ष 5,356 नए किसानों ने पंजीयन कराया है।

सर्व शिक्षा अभियान के 23 करोड़ के 250 स्कूल आठ साल से अधूरे

ग्राम पंचायतों को बनाई गई थी एजेंसियां

कोरबा। सर्व शिक्षा अभियान का शिक्षा विभाग में संविलियन को आठ साल हो चुका है। इन सात वर्षों में 23 करोड़ की लागत से बनने वाले 250 अधूरे स्कूलों का काम पूरा नहीं हुआ है। हैरत की बात यह है निर्माण कार्य को पूरा किए बगैर ही राशि जारी हो चुकी है। तत्कालीन समय में निर्माण के लिए ग्राम पंचायतों को एजेंसी बनाई गई थी।

पूर्व सरपंचों के कार्यकाल में निर्माणाधीन कार्यों की राशि को शिक्षा विभाग द्वारा न तो वसूली की गई और ना ही निर्माण के लिए नया प्राक्कलन तैयार किया गया। लंबे समय से अधूरे कार्य अब खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। अधूरे निर्माण के कारण छात्र-छात्राओं को तंग कमरों में पढ़ाई करनी पड़ रह है। सर्वशिक्षा अभियान मद से शिक्षा के विकास के लिए जारी राशि का आकलन किया जाने पर हासिल शून्य तो नहीं किंतु संतोष जनक भी नहीं है।

वर्ष 2009 से 2014 तक सर्व शिक्षा अभियान का संचालन हुआ। इस दौरान इस योजना के अंतर्गत स्कूल भवन, अतरिक्त, लैब, लायब्रेरी, दिव्यांगों के लिए रैंप आदि मिलाकर 6000 से भी अधिक कार्यो की स्वीकृति हुई। इन स्वीकृत कार्यों में 250 कार्य अब भी अधूरे हैं। मिर्माण किए बगैर राशि को आहरित किया जा चुका है। जिसे वसूल करने का साहस अब विभाग के बूते से बाहर नजर आ रहा है। यही वजह है कि लंबे समय से अधूरे निर्माण के स्कूल अतिरिक्त कक्ष अब खंडहर में तब्दील हो चुके है।

कोरबा विकासखंड के ग्राम भुलसीडीह के प्रायमरी स्कूल में निर्मित अतिरिक्त भवन सात साल से अधूरा पड़ा है। इसी तरह ग्राम नक्टीखार का भी अतिरिक्त कक्ष भवन की जर्जर दशा को छह साल हो चुकी है। पंचायती राज व्यवस्था के तहत प्रतिनिधि भी बदल चुके हैं लेकिन वर्तमान में इन स्कूलों की दशा ज्यों की त्यों बनी हुई। पंचायत चुनाव के दौरान कभी वर्तमान प्रतिनिधियों द्वारा अधूरे निर्माण कार्यों को प्रगति दिए जाने की बात कही गई थी।

सार्वजनिक उपक्रम के 374 अधिकारी कर्मचारी रह गए मतदान से वंचित

कोरबा। एसईसीएल समेत अन्य सार्वजनिक उपक्रम के 374 अधिकारी-कर्मचारी मतदान देने से वंचित हो गए। इन कर्मियों की चुनाव ड्यूटी लगाई गई थी, इसलिए उनसे डाक मतपत्र के लिए आवेदन लिया था, पर बाद में ड्यूटी नहीं लगाई। इससे कर्मी डाक मत पत्र व इवीएम दोनों से मतदान करने से वंचित रह गए।

जिले के चार विधानसभा कोरबा, कटघोरा, रामपुर और पाली तानाखार विधानसभा क्षेत्र के लिए शुक्रवार को मतदान की प्रक्रिया पूर्ण की गई। इस दौरान एसईसीएल कोरबा के अधिकारी- कर्मचारी अपने बूथों में मतदान करने पहुंचे तो कई के नाम पर डाक मतपत्र जारी होने की बातें सामने आई। इससे अधिकारी- कर्मचारी चौंक गए। उन्होंने जानकारी ली तो पता चला कि जिला निर्वाचन कार्यालय ने एसईसीएल समेत तमाम पब्लिक सेक्टरों से माइक्रो आब्जर्वर के लिए नाम मांगे थे।

इसमें एसईसीएल, एनटीपीसी व अन्य सार्वजनिक उपक्रमों से 474 अधिकारी- कर्मचारियों का नाम भेजा गया था। निर्वाचन विभाग के सभी कर्मियों को नियमानुसार प्रशिक्षण भी दिया गया। इस दौरान प्रशिक्षण में शामिल अधिकारी- कर्मचारी से डाक मत पत्र के लिए आवेदन भी लिया गया, लेकिन बाद में सिर्फ 100 कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई। एसईसीएल कोरबा के जीएम आफिस में पदस्थ लिपिक भुवनेश्वर का कहना है कि निर्वाचन संबंधी तमाम सूचनाएं विभाग के माध्यम से मिलती रही, लेकिन ड्यूटी नहीं लगाए जाने की सूचना दफ्तर से नहीं दी गई, इससे सभी अधिकारी- कर्मचारी निश्चित थे। उन्हें लग रहा था कि अब बूथों में जाकर ही मतदान करेंगे। इसके विपरीत बूथ में पहुंचने पर डाक मत पत्र जारी होने की बातें सामने आई।

उनका कहना है कि कर्मचारियों की चुनाव ड्यूटी नहीं लगाए जाने संबंधी सूचना अखबार में प्रकाशित करने की बात कही जा रही है। इससे कर्मचारियों के सामने ऊहापोह की स्थिति निर्मित हुई। नियमानुसार कार्यालय के माध्यम से ही ड्यूटी निरस्त होने की जानकारी दी जानी थी। बहरहाल मतदान नहीं कर पाने से 374 अधिकारी कर्मचारियों के चेहरे पर

गरियाबंद में सीएमओ ने साथियों संग मिलकर की स्वास्थ्यकर्मी की पिटाई, मौत

गरियाबंद/राजिम। गरियाबंद जिले में एक युवक की पीट-पीटकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। मृतक युवक स्वास्थ्यकर्मी है। हत्या के बाद सभी आरोपित मौके से फरार हो गए। आरोपितों में समोदा नगर पंचायत सीएमओ केशराम साहू भी शामिल है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है।

दरअसल, घटना गरियाबंद के फिंगेश्वर थाना क्षेत्र अंतर्गत सेंदर गांव की है। जानकारी के अनुसार गोहरापदर में स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ नेमसिंह ध्रुव की मामूली बात को लेकर समोदा नगर पंचायत सीएमओ केशराम साहू और उसके साथियों ने जमकर पिटाई कर दी।

चुनाव के बाद कामकाज आया पटरी पर, 150 अधिकारी अब तक अनुपस्थित

भिलाई। विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होने के बाद निगम में जनहित के कार्यों को पटरी पर लाने के लिए निगम आयुक्त के निर्देश पर अपर आयुक्त ने निगम मुख्यालय के सभी विभागों का औचक निरीक्षण किया। विभाग प्रमुख व कर्मचारियों की उपस्थिति की जांच की तो 150 अधिकारी व कर्मचारी अपने विभाग में अनुपस्थित पाए गए।

निगम आयुक्त रोहित व्यास ने चुनाव के लिए मतदान होने के बाद अधिकारी कर्मचारी अपने कार्य पर मुस्तैद रह कर जनहित के कार्यों को गति प्रदान करें, इस उददेश्य को लेकर अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी को निगम मुख्य कार्यालय सुपेला के सभी विभागों का अवलोकन कर अधिकारी व कर्मचारियों की कार्यालयीन समय 10 बजे उपस्थिति की जांच करने निर्देश दिए। जांच में विभाग प्रमुख सहित 150 अधिकारी कर्मचारी अपने विभाग में अनुपस्थित रहे। अपर आयुक्त ने डाटा सेंटर को सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों का निष्ठा ऐप में जॉच कर देर से आने वाले अधिकारी व कर्मचारियों की सूची तैयार कर आयुक्त के समक्ष पेश करने को कहा है। इसी प्रकार स्थापना अधीक्षक को उपस्थिति पंजी की जांच कर अनुपस्थित रहने वालों को नोटिस दिए जाने का निर्देश दिए है।

पंजे के निशान व पेड़ों पर खरोंच देख करेंगे वन्य प्राणियों की पहचान

महांत शुरू होगी एटीआर में फोर फेस मानिटरिंग, प्रशिक्षण के बाद कैमरों का वितरण

बिलासपुर। अचानकमार टाइगर रिजर्व में के अंदर बाघ के अलावा और कितने वन्य प्राणी है, इसका आकलन करने के लिए प्रबंधन फोर फेस मानिटरिंग करेगा। इसी माह के अंत तक शुरू होने वाली इस गणना के दौरान पहले सात दिन वन अमला पंजे के निशान, पेड़ों पर खरोंच, मल और कील देखकर वन्य प्राणियों की पहचान करेंगे। सात दिन तक चलने वाली इस विधि के बाद ट्रैप कैमरे की मदद ली जाएगी।

बेहतर गणना के लिए इस बार दो महीने तक कैमरे लगाने का निर्णय प्रबंधन ने लिया है। किसी भी टाइगर रिजर्व के लिए बाघ व अन्य वन्य प्राणियों की गणना बेहद जरूरी होती है। यह प्रविधान है। गणना दो तरीके से होती है। एक वह विधि है, जो चार साल में एक बार होती है। वहीं फोर फेस मानिटरिंग साल में दो बार होती है। दो बार होने वाली यह गणना गर्मी और ठंड के समय की जाती है।

एक हो चुकी है। अब ठंड में होने वाली गणना होनी है। इसको लेकर निर्देश भी जारी हो गया है। फोर फेस मानिटरिंग सात दिन होती है। जिसमें पहले तीन दिन ट्रैल लाइन पर बाघों के पंजों के निशान आदि देखे जाते हैं। इसके बाद ट्रांजिट लाइन में वन अमला चलकर गणना करता है। ट्रांजिट दो किमी का होता है। इसमें वन कर्मी व अधिकारी पैदल चलकर पंजों के निशान, वन्य प्राणियों द्वारा पेड़ों में किए गए खरोंच, मल, अवशेष सभी बारीकी से देखते हैं।

सैंपल भी एकत्र किया जाता है, ताकि उसकी जांच कर वन्य प्राणी की पहचान किया जा सके। इस प्रक्रिया के बाद ट्रैप कैमरे से गणना की जाती है। पहले चिंहित जगहों पर 25-25 दिनों के लिए गणना करते थे। इस बार दो महीने तक कैमरे लगाने की योजना है। इससे गणना और बेहतर ढंग से हो सकेगी। इन कैमरे के सामने जो भी गुजरता है आटोमेटिक उनकी फोटो क्लिक होकर चिप पर सेव हो जाती है।

प्रशिक्षण के बाद कैमरों का वितरण

इस गणना की रिपोर्ट सीधे राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को जाती है। इसलिए लापरवाही न करने के लिए सख्त चेतावनी दी जाती है। इसके अलावा कोई चूक न हो इसलिए वन अमले को एक्सपर्ट प्रशिक्षण भी देते हैं। इस बार यह विधि अपनाई जा रही है। इसके बाद जिन- जिन जगहों पर कैमरे लगने हैं, उस क्षेत्र के वनकर्मियों को कैमरे का वितरण किया जाएगा। हर तीन दिन में कैमरे के चिप को निकालकर फोटो को सेव किया जाता है।

ध्वनि प्रदूषण, साइलेंस ज़ोन घोषित कर कार्रवाई के निर्देश

बिलासपुर।डीजे से हो रहे ध्वनि प्रदूषण को लेकर हाईकोर्ट की स्वतः संज्ञान जनहित याचिका के साथ हस्तक्षेप याचिका पर हाईकोर्ट ने सोमवार सुनवाई की। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा, जस्टिस अरविंद कुमार चन्देल की युगल पीठ ने शासन को प्रकरण में कार्रवाई की जानकारी देने कहा।

कोर्ट ने यह भी निर्देश दिए कि शहरों में साइलेन्स जोन घोषित कर डीजे प्रतिबंधित करना चाहिए। डीजे के कानफोडू शोर से हो रही दिक्कतों पर चीफ जस्टिस ने दो माह पूर्व 29 सितंबर को स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट ने उच्चतम न्यायालय तथा छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट द्वारा इस विषय पर दिए गए पूर्व के आदेशों का उल्लेख करते हुए इनके पालन के संबन्ध में मुख्य सचिव को रिपोर्ट देने का अंतरिम आदेश पारित किया था।

सुनवाई के दौरान युगल पीठ ने नाराजगी जाहिर करते हुए छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य सचिव को यह बताने को कहा कि उत्सवों के अवसर के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों, डीजे द्वारा उत्पन्न ध्वनि प्रदूषण के खतरे को खत्म करने के लिए क्या प्रयास किए? कोर्ट ने इस संबंध में एक विस्तृत शपथपत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। इस पर शासन ने नियम बनाकर डीजे प्रतिबन्धित करने की जानकारी दी। चीफ जस्टिस ने माना कि बिलासपुर शहर में ध्वनि प्रदूषण की वर्तमान स्थिति बदहाल है जो कि समाचारों की कतरनों से भी स्पष्ट है।

यह जिम्मेदार राज्य अधिकारियों के अपमानजनक कृत्य के अलावा और कुछ नहीं है। वे ध्वनि प्रदूषण के खतरे को रोकने में कोई भी प्रयास करने में विफल रहे हैं । सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ इस न्यायालय द्वारा विभिन्न आदेश व निर्देश पारित करने के बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। पिछले साल 19 फरवरी को भी हाईकोर्ट ने डीजे से प्रदूषण पर दायर एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए थे।

महाधिवक्ता कार्यालय को शासन से यह दिशा निर्देश लेने को कहा था कि कोर्ट के आदेश पर क्या कार्रवाई की जा रही है। शहर में बज रहे कानफोडू डीजे के कारण तत्कालीन कलेक्टर तथा पुलिस अधीक्षक के विरुद्ध अवमानना याचिका पर कोर्ट ने यह आदेश दिया था।

आयुष्मान कार्ड इस इलाज कराने के बाद मरीज से वसूले 67 हजार

अस्पताल को तीन माह के लिए निलंबित कर दिया

राजनांदगांव। आयुष्मान कार्ड से इलाज होने के बाद भी मरीज से 67 हजार 382 रुपए वसूल किए जाने पर अस्पताल को तीन माह के लिए निलंबित कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार चिखली में संचालित संजीवनी नर्सिंग होम में आयुष्मान कार्ड से इलाज के बाद मरीज से नकदी राशि लेने का आरोप लगा था। जांच में पुष्टि के बाद प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना अंतर्गत अस्पताल का पंजीयन तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया है। डोंगरगढ़ क्षेत्र के ग्राम शिवपुरी निवासी संतोष कुमार वर्मा की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई।

संजीवनी नर्सिंग होम में उन्होंने अपने दादा खेमचंद वर्मा को आयुष्मान से उपचार के लिए भर्ती कराया था। प्रबंधन द्वारा पूरा इलाज आयुष्मान कार्ड से होने की बात कही गई, लेकिन बाद में अतिरिक्त राशि की मांग की, जिसे नकद और ऑनलाइन माध्यम से दिया गया है। शिकायत मिलने पर जांच की गई। जांच में जो तथ्य सामने आया, उसे उच्चाधिकारियों को भेजा गया था। उस आधार संजीवनी नर्सिंग होम को इस योजना से तीन महीने के लिए सस्पेंड किया गया है।

- डॉ. बीएल तुलावी, नोडल अधिकारी

शहर में प्रवेश करने पर लगती है एंट्री फीस, नियमों की आड़ में हो रही अवैध वसूली

राजनांदगांव। शहर के प्रमुख चौक-चौराहों से लेकर अंदरुनी भाग में ट्रैफिक व्यवस्था बदहाल है। चौक-चौराहों से ट्रैफिक जवान नदारद हैं। जबकि आऊटर में जांच के नाम पर लगातार चालानी कार्रवाई और अवैध वसूली की शिकायत है। शहर के आउटर में प्वाइंट लगाकर रोजाना वाहनों की जांच की जा रही है। जांच के दौरान कई तरह के नियमों का हवाला देकर मालवाहकों पर अनाप-शनाप चालानी कार्रवाई कर रहे हैं। सौ से अधिक बिंदुओं पर नियमों में उलझाकर वाहनों पर किसी तरह से चालानी कर रहे हैं। कई वाहन चालकों को बिना रसीद दिए ही राशि वसूल रहे हैं। शहर में प्रवेश के पहले एंट्री फीस ली जा रही है।

वहां भारी वाहनों को रोका जा रहा था, कागजात पूरा होने के बाद कई तरह के यातायात नियमों को बताकर चालानी कार्रवाई की जा रही थी। कुछ भारी वाहन चालकों ने बताया कि वे बाहरी राज्य की गाड़ी चला रहे हैं।

शहर के अनेक जगहों पर ना ही सिंगल न कोई व्यवस्था, लगता है हमेशा जाम

राजनांदगांव। शहर का दायरा लगातार बढ़ रहा है। साथ ही यहा रहवासी और सडक् पर गाडियों की संख्या भी बढ़ गई है। इसके चलते शहर के मुख्य मार्गो में यातायात का दबाव भी बढ़ रहा है। इन परिस्थितियों में शहर के आउटर में कई जगह ऐसे हैं, जहां आए दिन ट्रैफिक जाम की स्थिति बन रही है। इन जगहों में न ही ट्रैफिक सिग्नल लगे हैं और न ही यातायात का कोई जवान व्यवस्था संभाल रहा है। यही कारण है कि बेतरतीब यातायात व्यवस्था दुर्घटनाओं को आमंत्रण दे रहा है।

बता दें कि शहर में फ्लाईओवर के नीचे ही चौक-चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल लगे हैं, लेकिन इसमें भी आए दिन खराबी की समस्या रहती है। यहां ट्रैफिक जवान की गैरमौजूदगी में नियमों का पालन भी नहीं होता। गाडियां बेतरतीब निकलती है। पैदल और दो पहिया वाले रेड लाइट में भी सडक् पार करते हैं, इससे कई बार दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। पिछले दिनों मोपेड पर सवार मोतीपुर निवासी एक कॉलेज छात्रा की भारी वाहन की चपेट में आने से मौत भी हुई थी।

शहर में बढ़ती आबादी के बीच हाइवे में आरके नगर चौक, मेडिकल कॉलेज अस्पताल चौक, इधर शहर में वीआईपी मार्ग महामाया चौक, नंदई चौक, कुआं चौक, गंज चौक, लखोली चौक, फिर रायपुर रोड में रामदरबार मंदिर के पास ट्रैफिक सिग्नल लगाने की आवश्यकता है। निगम द्वारा यहां सिग्नल लगाने के लिए बजट में प्रावधान रखा गया था, लेकिन निगम प्रशासन यहां सिग्नल लगाना भूल गया। वहीं यातायात विभाग द्वारा भी इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उधर बाइपास में फ्लाईओवर के नीचे फरहद चौक, मोहारा चौक, लखोली-कन्हारपुरी चौक और पार्रीनाला चौक के पास भी चौराहा होने के कारण ट्रैफिक का दबाव रहता है। इन चौक-चौराहों में ही ठेला-खोमचा होने के कारण भी सडकें संकरी हो जाती है। दुकानदारी के चलते वहां गाडियां पार्किंग की जाती है।

यातायात विभाग के प्रभारी व डीएसपी हेमप्रकाश नायक ने बताया कि शहर में यातायात के बढ़ते दबाव को देखते हुए चार जगहों में ट्रैफिक सिग्नल और सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए प्रपोजल भेजा गया है। स्वीकृति मिलते ही जल्द व्यवस्था होगी। इसके तहत आरके नगर चौक, राज इंपीरियल होटल चौक, फरहद चौक और गंज चौक शामिल है।

संजारी बालोद में सबसे ज्यादा 84.83 फीसदी व सबसे कम डौंडीलोहारा में 81.88 प्रतिशत मतदान हुआ

बालोद. जिले में शुक्रवार को हुए मतदान की अंतिम व फाइनल रिपोर्ट निर्वाचन आयोग ने जारी कर दी है। निर्वाचन आयोग के मुताबिक जिले में इस बार 83.51 प्रतिशत मतदान हुआ, जो बीते 2018 विधानसभा चुनाव से एक प्रतिशत ज्यादा है। 2018 के विधानसभा चुनाव में जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों में मिलाकर कुल 82.43 प्रतिशत मतदान हुआ था।

2 लाख 92 हजार 131 महिला मतदाताओं ने किया मतदान

जिले के तीनों विधानसभा में सबसे ज्यादा मतदान संजारी बालोद विधानसभा में 84.83 प्रतिशत तथा सबसे कम मतदान डौंडी लोहारा विधानसभा में 81.88 प्रतिशत हुआ। वहीं गुंडरदेही विधानसभा में 83.76 प्रतिशत मतदान हुआ। इस चुनाव में मतदान करने में महिला मतदाता पुरुष मतदाताओं से आगे रहीं। जानकारी के मुताबिक जिले में कुल 6 लाख 88 हजार 954 मतदाता हैं, जिसमें से 5 लाख 75 हजार 326 मतदाताओं ने मतदान किया। इस चुनाव में 2 लाख 83 हजार 194 पुरुष मतदाताओं तथा 2 लाख 92 हजार 131 महिला मतदाताओं ने मतदान किया।

कहीं पांच बजे के पहले मतदान तो कहीं रात 7-8 बजे तक हुआ मतदान

जिले में मतदान को लेकर मिलाजुला असर देखने को मिला। अधिकांश जगहों पर समय पर मतदान हुआ। लेकिन जिले के कुछ ऐसे मतदान केंद्र रहे, जहां धीमा मतदान व मशीन में खराबी की वजह से 5 के बजाए 7 से 8 बजे तक मतदान हुआ।

अर्जुनी व टेकापार में रात 8 बजे तक हुआ मतदान

जिले के ग्राम भरदा मतदान केंद्र में शाम 6 बजे करीब वोटिंग मशीन में खराबी आ गई, जिसके बाद तत्काल मशीन बदली गई। नई मशीन लगाने के बाद फिर से मतदान हुआ क्योंकि यहां मतदान केंद्र में शाम 5 बजे ताला लगा दिया। वहीं मतदान केंद्र के अंदर लगभग 100 से अधिक मतदाता थे, जिन्होंने मतदान किया। वहीं अर्जुनी व टेकापार में भी लगभग 8 बजे तक मतदान पूर्ण हुआ।

बीते 2018 के चुनाव में हुआ था 82.81 प्रतिशत वोटिंग

मिली जानकारी के मुताबिक जिले के तीनों विधानसभा में बीते 2018 के विधानसभा चुनाव में जिले में 82.81 प्रतिशत मतदान हुआ था। जिसमें हर विधानसभा में लगभग 80 प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ था।

31 प्रत्याशियों की किस्मत का पिटारा ईवीएम में कैद, कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रॉन्ग रूम में की जा रही निगरानी

बालोद. जिले के तीनों विधानसभा में 17 नवंबर को हुए मतदान के बाद जिले की तीनों विधानसभा के 31 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। मतदान के बाद शुक्रवार-शनिवार की दरमियानी रात सभी ईवीएम को कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच स्ट्रॉन्ग रूम लाया गया। अब वोटिंग मशीनें पाकुभाट स्थित स्ट्रॉन्ग रूम में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ की तगड़ी निगरानी व सुरक्षा में सुरक्षित रखी गई हैं। वहीं राजनीतिक दल भाजपा, कांग्रेस व अन्य प्रत्याशी अपने समर्थकों को ईवीएम की निगरानी के लिए रखेंगे।

14 दिन बाद प्रत्याशियों के भाग्य का आएगा फैसला

अब यह ईवीएम 14 दिन बाद आगामी 3 दिसंबर को मतगणना के दिन खोली जाएंगी व बारी-बारी से वोटिंग मशीन में पड़े वोटों की गिनती

की जाएगी, जिसकी तैयारी अब निर्वाचन आयोग करने जा रहा है। क्योंकि मतगणना में ज्यादा दिन का समय बचा ही नहीं है।

तगड़ी सुरक्षा, स्ट्रॉन्ग रूम की खिड़कियां ईंटों से पैक

पाकुरभाट स्थित स्ट्रॉन्ग रूम को पूरे बीएसएफ के जवानों ने अपने कब्जे में लिया है। यहां रखे वोटिंग मशीनों की सुरक्षा कर रहे हैं। साथ ही पूरा परिसर सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में है। यही नहीं पूरे स्ट्रॉन्ग रूम के सभी खिड़कियों को ईंट से पैक किया गया है। यहां सुरक्षा ऐसी है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता।

बिना पास के प्रवेश नहीं

स्ट्रॉन्ग रूम परिसर में बिना पास के आपको एंट्री नहीं मिलेगी। अधिकारियों को भी पास व आईडी कार्ड दिखाना होगा। लेकिन बिना कारण के यहां तैनात बीएसएफ के जवान घुसने नहीं देंगे। वहीं निर्वाचन आयोग ने वोटिंग मशीन को कड़ी सुरक्षा व निगरानी के बीच रखा है। बाहर एलईडी टीवी लगाई गई हैं, जहां 24 घंटे लाइव स्थिति दिखाई जाएगी। प्रत्याशी व उनके चुनिंदा समर्थक निर्वाचन आयोग की नई गाइडलाइन के तहत यहां आकर स्थिति देख सकेंगे।

मोबाइल पर लगातार गेम खेलने और टीवी देखने से बच्चों की आंखें हो रही कमजोर

स्कूल में बच्चों के आंखों की जांच की गई।

बालोद. घरों में मोबाइल पर लगातार गेम खेलना, मोबाइल देखना व लगातार टेलीविजन देखने से बचपन में ही बच्चों की नजर कमजोर हो रही है। जिला स्वास्थ्य विभाग के नेत्र रोग विशेषज्ञ की टीम स्कूल खुलने के बाद नए शिक्षण सत्र में नेत्र जांच अभियान चला रही है। अभी तक कुल 212 स्कूलों में नेत्र जांच शिविर लगाकर बच्चों के आंखों की जांच की है। 574 बच्चों में दृष्टिदोष पाए गए हैं।

नेत्र विभाग की टीम ने इस साल कुल 292 स्कूलों में नेत्र जांच शिविर लगाया। स्कूलों के कुल 22,713 बच्चों का नेत्र परीक्षण किया गया। 574 बच्चों में दृष्टिदोष पाया गया है। जिन बच्चों की आंखों में ज्यादा परेशानी है, उन्हें निःशुल्क चश्मा भी दिया जा रहा है।

नेत्र विभाग के चिकित्सक अनिल कुमार सिन्हा ने बच्चों व पालकों से अपील भी की कि छोटे बच्चों को ज्यादा मोबाइल व टेलीविजन का आदि न बनाएं। बच्चे मोबाइल व टेलीविजन के आदि हो गए हैं। यह घातक साबित हो रहा है। बच्चों को भी सावधानी बरतनी होगी। जांच में कुछ बच्चों में नजर कमजोर होना, दृष्टि सामान्य से कम होना व नेत्र एलर्जी होना, अधिक चाकलेट खाने से दांतों में केविटी होना, कुछ बच्चों का उम्र के हिसाब से वजन कम पाया गया। कुछ में रक्त की भी कमी पाई गई।

नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. अनिल कुमार सिन्हा ने बताया कि आंखों में नजर का विकास सात वर्ष की आयु तक होता है।

लोकतंत्र के महायज्ञ में आहुति देने घरों से नहीं निकले 1 लाख 77 हजार वोटर्स

जांजगीर चांपा। लोकतंत्र के महायज्ञ में इस बार जिले में 1 लाख 77 हजार वोटर्स आहुति देने घरों से बाहर ही नहीं निकले। जिले के कुल 6 लाख 54 हजार 394 मतदाताओं में से 4 लाख 77 हजार 285 वोटर्स ने ही मतदान किया।

ओवरआल जिले में 72.94 प्रतिशत मतदान हुआ। सबसे ज्यादा मतदान अकलतरा विधानसभा में हुआ। इसके बाद जांजगीर-चांपा विधानसभा रहा। सबसे कम मतदान पामगढ़ में हुआ। हालांकि मतदान जागरूकता को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा कई गतिविधियों का आयोजन जिलेभर में किया गया। मतदान करने में पुरुष वोटर्स आगे रहे। महिला वोटर्स की तुलना में 4654 अधिक पुरुष वोटर्स ने मतदान किया। हालांकि कुल पुरुष और महिला मतदाताओं के हिसाब से कुल पड़े वोटों की संख्या देखे तो महिला वोटर्स आगे हैं। जिले में कुल पुरुष वोटर्स 3 लाख 32 हजार 067 हैं। इनमें से 2 लाख 40 हजार 960 मतदाताओं ने ही अपने मताधिकार का उपयोग किया। इस तरह ओवरआल पुरुष वोटर्स मतदान का प्रतिशत 75.98 रहा। जबकि जिले में कुल महिला वोटर्स की संख्या 3 लाख 22 हजार 309 हैं वहीं 2 लाख 36 हजार 315 महिलाओं ने वोट डाले। महिला वोटिंग का कुल प्रतिशत 73.32 रहा। इस तरह महिला मतदान का प्रतिशत पुरुष मतदान की तुलना में 0.76 रहा। गौरतलब है कि दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव के लिए हुए मतदान में जिले के तीनों विधानसभा अकलतरा, जांजगीर-चांपा और पामगढ़ में कुल 72.94 प्रतिशत वोट पड़े। कुल 6 लाख 54 हजार 394 मतदाताओं में से 4 लाख 77 हजार 285 मतदाता ही अपने घरों से वोट देने बाहर निकले।

पुरुष मतदाताओं की संख्या अधिक

जिले के तीन विधानसभा क्षेत्रों में महिला वोटर्स की तुलना में पुरुष वोटर्स की संख्या अधिक है। लेकिन इसके बावजूद भी मतदान करने में महिला वोटर्स आगे नजर आई। अकलतरा विस महिला वोटर्स की तुलना में पुरुष वोटर्स की संख्या 3508 अधिक है। इसी तरह जांजगीर-चांपा विस में महिला वोटर्स की तुलना में पुरुष वोटर्स 3022 तो पामगढ़ विस में 3228 वोटर्स अधिक है। यानी सभी विधानसभा में महिला वोटर्स की संख्या पुरुष मतदाताओं से कम होने के बावजूद वोट डालने में महिलाओं की भागीदारी ज्यादा रही। जबकि चुनाव मैदान में महिला प्रत्याशियों की भागीदारी पुरुषों की तुलना में कम है। बड़े दलों के द्वारा भी महिलाओं की ज्यादा पुरुष प्रत्याशियों पर ही ज्यादा भरोसा जताया जा रहा है।

49 लाख की निर्माणाधीन नाली ढही, गुणवत्ता पर उठे सवाल

जांजगीर चांपा। शहर के नेताजी चौक से कचहरी चौक तक बनाई जा रही करीब 49 लाख रुपए की निर्माणाधीन नाली का कुछ हिस्सा ढह गया। इससे निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर भी सवाल उठने लगा है। दिवाली के दौरान हड़बड़ी में काम कराने को इसकी वजह माना जा रहा है लेकिन नपा के जिम्मेदारों का कहना है कि काम के दौरान ट्रैक्टर से निर्माण सामग्री और मिट्टी फिलिंग के कारण नाली का कुछ हिस्सा गिरा है।

गौरतलब है कि नगरपालिका के द्वारा नेताजी चौक से कचहरी चौक तक दोनों ओर अतिक्रमण हटाने के बाद दुकानों से लगकर नाली निर्माण का काम ठेकेदार के माध्यम से कराया जा रहा है। इसमें वर्तमान में एक ओर नाली बनाने का काम प्रगति पर है। जहां बुधवार की सुबह बंसल ट्रेडर्स के आगे बनाई गई नाली और स्लैब अचानक ढह गई और नीचे जा गिरी। जिसे जेसीबी के माध्यम से मलबा को बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि दिवाली के दौरान भी निर्माण कार्य जारी था। ऐन त्योहारी सीजन के दौरान दुकानदारों को काफी परेशानी हो रही थी। जल्दी काम कराने दबाव भी डाला जा रहा था।

जिले में मैरिज गार्डन, बिना रजिस्ट्रेशन व पार्किंग के हो रहे संचालित

जांजगीर चांपा। शहर में अतिक्रमण रोकने ट्रैफिक पुलिस द्वारा की गई तमाम कोशिशों पर नवरात्र व दिवाली को व्यापारियों ने पानी फेर दिया। ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए दीपावली के पूर्व सारे प्रयास निरर्थक साबित हुए। पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने से लोग सड़क में ही अपने वाहन को पार्क कर दिए। इस वजह से शाम से ही कचहरी चौक से लेकर नेताजी चौक व रेलवे स्टेशन तक जाम की स्थिति हर 15 से 20 मिनट में बनती रही। अब त्यौहारी सीजन निपटने के बाद शादी सीजन शुरू होने वाला है। 23 को देवउठनी के साथ शादी शुरू हो जाएंगे। मैरिज गार्डन और विवाह घरों, होटलों की बुकिंग शादियों के लिए पहले हो गई है। शादियों के सीजन में शहर के मैरिज गार्डनों के कारण लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ेगा। क्योंकि शहर सहित जिले भर में नियमों को ताक में रखकर चल रहे इन मैरिज गार्डनों में पार्किंग की कोई व्यवस्था भी नहीं है। जिसके चलते मुख्य मार्गों पर बने इन मैरिज गार्डनों के बाहर यातायात व्यवस्था हर साल की तरह इस साल भी बिगड़ने की संभावना है। विवाह समारोह में शामिल होने वाले पार्किंग नहीं होने से लोग रोड पर ही वाहन खड़े करने को मजबूर होते हैं। कई बार तो इन मैरिज गार्डनों के बाहर खड़े वाहनों की वजह से लगे जाम के कारण विवाद की स्थितियां निर्मित होती है। मैरिज गार्डन और होटलों में पॉर्किंग नहीं होने से सड़कों पर जाम लगेगा। लोगों को निकलने में काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। बता दे कि शहर में 20 से अधिक व अंचलभर में 100 से अधिक मैरिज गार्डन है। कुछ रजिस्ट्रेशन हो सकते है। बाकी बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे इन मैरिज गार्डनों पर प्रशासन कभी कोई कार्रवाई नहीं करता। सड़को में गंदगी फैलाने के बाद भी जुर्माने की कार्रवाई नहीं की जाती।

कचरा नष्ट करने की सुविधा तक नहीं

सुप्रीम कोर्ट के नियम के अनुसार मैरिज गार्डन से निकलने वाले कचरे को गार्डन संचालक को ही नष्ट कराना अनिवार्य है, लेकिन रिहायशी क्षेत्रों के मैरिज गार्डन व होटलों के आसपास देखा जाए, यहां का कचरा बड़ी मात्र में देखने को मिल सकता है। अधिकतर गार्डनों में कचरा उचित ढंग से नष्ट करने की सुविधा तक नहीं है। कई शादी भवन संचालक तो पास में ही कचरा को फेंक देते हैं। इससे मोहल्लेवासियों का रहना मुश्किल हो जाता है।

पार्किंग के बिना कैसे मिल गई निर्माण की अनुमति

मैरिज गार्डन के लिए पहले तो व्यवसायिक भूखंड का डायवर्सन राजस्व विभाग से कराना होता है। इसके बाद नगर पालिका से भवन निर्माण की अनुमति लेना पड़ती है। नगर पालिका में नक्शा पेश करने के साथ ही सारे नियमों को भी पालन करना पड़ता है। नगर पालिका अधिकारी, इंजीनियरों द्वारा पूरा मौका मुआयना करने के बाद ही निर्माण अनुमति दी जाती है। अब सवाल ये उठता है कि जब मैरिज गार्डनों के पास पार्किंग व्यवस्था ही नहीं है तो उन्हें अनुमति कैसे दे दी गई।

स्टेशन परिसर में ठेकेदार की मनमानी से यात्री हो रहे परेशान

रायगढ़। रेलवे स्टेशन के साइकिल स्टैंड का जब से ठेका बदला है, तब से ठेकेदार के मनमानी के चलते यहां आए दिन विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इसको लेकर स्टेशन आने वाले यात्रियों में काफी नाराजगी देखी जा रही है।

करीब 10 माह पहले रेलवे स्टेशन के साइकिल स्टैंड व कार स्टैंड का ठेका बदला गया है। ऐसे में नए ठेकेदार हमेशा से विवादों में रहा है। जिससे पूर्व में काफी विवाद के बाद कुछ दिनों तक स्थिति सामान्य थी, लेकिन अब फिर से मनमानी बढ़ने के कारण लोगों में आक्रोश पनपने लगा है। इस संबंध में स्टेशन आने वाले यात्रियों की मानें तो रेलवे विभाग द्वारा इस बार ठेका सायकल स्टैंड का दिया गया है, लेकिन ठेकेदार के कर्मचारी पूरे स्टेशन परिसर से पैसे वसूल रहे हैं।

हालांकि स्टेशन के बाद सर्कुलेटिन एरिया को ठेका से मुक्त रखा गया है, ताकि थोड़ी देर के लिए आने वाले यात्री वहां खड़ा होकर अपने परिजन को रिसिव कर सके, लेकिन ठेकेदार के कर्मचारी अब सर्कुलेटिन एरिया से भी वसूली करते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही जो परिजन पैसे देने से मना करते हैं तो उनके साथ विवाद की स्थिति उत्पन्न कर दे रहे हैं। जिसको लेकर लोगों में काफी नाराजगी देखी जा रही है।

धान के उठाव के लिए डीओ काटने के मामले में सारंगढ़ पीछे

रायगढ़। प्रदेश में धान खरीदी को शुरू हुए 19 दिन बीत गया है। शुरूआती दौर में आवक कम है, लेकिन खरीदी व कस्टम मिलिंग के लिए प्रदाय आकड़ों पर गौर किया जाए तो धान खरीदी में जहां सारंगढ़ जिला रायगढ़ से आगे है तो वहीं समितियों से धान के उठाव के लिए डीओ काटने के मामले में सारंगढ़ पीछे है।

विदित हो कि कुछ समय पूर्व सारंगढ़ के राइसमिलर एसोसिएशन ने कलेक्टर सहित संबंधित अधिकारियों के समक्ष पूर्व की लंबित राशि को प्रदाय करने की मांग की थी, पिछले दो साल के लंबित राशि का भुगतान न होने के कारण आक्रोश जताते हुए धान का उठाव न करने की बात कही थी।

हालांकि लंबित भुगतान की समस्या जस की तस है ऐसे में धान खरीदी व कस्टम मिलिंग के लिए प्रदाय किए गए धान की मात्रा के आकड़ों पर गौर किया जाए तो रायगढ़ में 5 हजार 110 क्विंटल धान की खरीदी पिछले 19 दिनों में की गई है जिसमें से 930 क्विंटल धान मिलर को प्रदाय दिखाया गया है जबकि नवगठित सारंगढ़ जिले की स्थिति पर नजर डाला जाए तो यहां 50 हजार 720 क्विंटल की खरीदी हो चुकी है जिसमें से अभी तक मिलरों को एक दाना धान कस्टम मिलिंग के लिए प्रदाय नहीं किया गया है। सूत्रों की माने तो मिलर यहां अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं यही कारण है कि कस्टम मिलिंग के लिए डीओ कटवाने अभी तक मिलरों ने रिक्रेस्ट भी नहीं डाला है।

आवक बढ़ने पर होगी समस्या

नवगठित सारंगढ़ जिले के करीब-करीब सभी समितियों में बोहनी हो चुकी है दीपावली त्योहार के बाद धान की कटाई भी तेज हो गई है जिसके कारण आगामी दिनों धान खरीदी केंद्रों में आवक बढ़ेगी। आवक बढ़ने के बाद भी यही स्थिति बनी रही तो आने वाले दिनों में समस्या बढ़ेगी और खरीदी प्रभावित हो सकती है।

खरीफ विपणन वर्ष 2022 में कस्टम मिलिंग के लिए धान का उठाव करने के बाद रायगढ़ व सारंगढ़ जिले के दर्जन भर से अधिक मिलरों ने अब तक कस्टम मिलिंग का पूरा चावल जमा नहीं किया है। इसमें सारंगढ़ जिले के मिलर अधिक है अब ऐसे मिलरों का पुराना चावल जमा हुए बगैर पंजीयन संभव नहीं है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वोट डालने 40 मिनट तक खड़े रहे कतार में

भिलाई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शुक्रवार को पाटन विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कुरूदढीह के प्राथमिक स्कूल भवन में मतदान करने परिवार के साथ पहुंचे। ग्राम कुरूदढीह में मौजूद अपने निवास से वे पैदल ही मतदान करने निकले। वोटिंग करने के लिए वे कतार पर लग गए, करीब 40 मिनट तक कतार में रहने के बाद वोटिंग किए। मुख्यमंत्री के साथ पत्नी, मुक्तेश्वरी बघेल, बहन, बेटियां, बहू और बेटा चैतन्य बघेल ने भी मतदान किया। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए।

कांग्रेस इस बार 75 पार

मतदान करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस इस बार 75 से अधिक सीटों पर जीत दर्ज करेगी। छत्तीसगढ़ के लोगों को कांग्रेस के वादे पर भरोसा है। भाजपा ने जो वादा किया, उसे निभाया नहीं। वहीं मुख्यमंत्री के पुत्र चैतन्य बघेल ने कहा कि मुख्यमंत्री व कांग्रेस के तमाम लीडर जैसा कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस की सीट 75 पार जाएगी। उन्होंने कहा कि पाटन के तमाम बूथ का दौरा किए हैं, वोटरों में खासा उत्साह है।

जनता प्यार से कहती है कका

मुख्यमंत्री की बेटी ने मतदान करने के बाद बताया कि पापा ने बहुत ईमानदारी से जनता की सेवा की है। उनको जनता प्यार से कका कहती है। लोगों ने भूपेश है, तो भरोसा है का नारा दिया है। यही वजह है कि प्रदेश की महिलाओं ने कांग्रेस के वादे पर मुहर लगाया है। बहू ने कहा कि कोविड के समय जो काम मुख्यमंत्री ने किया, उसकी वजह से दूसरे राज्यों से छत्तीसगढ़ की स्थिति बेहतर रही। जनता को इस वजह से मुख्यमंत्री और कांग्रेस सरकार पर पूरा भरोसा है।

कवर्धा जिले में तेजी से पैर पसार रहा डेंगू

कवर्धा। कवर्धा जिले में डेंगू जैसे जानलेवा बीमारी पैर पसर रहे हैं।

समस्या से जूझ रहे वार्डवासी अपनी परेशानी बताने के लिए वार्ड पार्षद से लेकर अध्यक्ष और पालिका के प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन व्हीव्हीआई का चोले पहिने नगर पालिका प्रशासन के जिम्मेदार न तो किसी का फोन रिसिव करते और न ही किसी से बात करे। ऐसे में वार्ड के गलियों से लेकर नालियों में गंदगी बजबजा रही है, जिसमें डेंगू का लार्वा पनप रहा है। ऐसे में वार्डवासियों का बीमार होना तो तय है।

हम बात करे रहे वार्ड क्रमांक 26 की, जहां मुख्य मार्ग किनारे कचरों का ढेर लगा हुआ है। वहीं सड़क किनारे नालियां तो बनी है, लेकिन नियमित सफाई नहीं हुई है। इसके चलते नालियां जाम हो चुकी है। ऐसे में निस्तारी का पानी नाली छोड़ गलियों में बहने गली है। जब मुख्य मार्ग किनारे नालियों की ऐसी स्थिति है, तो अंदरुनी बस्ती की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। कवर्धा नगर पालिका मुट्ठी भर क्षेत्र में बसा हुआ है। इसके बाद भी प्रशासन समुचित व्यवस्था नहीं कर पा रहा है। शहर के अधिकांश वार्डों में साफ-सफाई का बुराहाल है।

साफ सफाई की समुचित व्यवस्था न होने के चलते शहर में चारों तरफ गंदगी का आलम पसरा हुआ है। इससे नगर पालिका अमले को कोई सरोकार नहीं है। इसके चलते मच्छरों का प्रकोप देखने को मिल रहा है। कई वार्ड में डेंगू के संभावित मरीज मिले हैं, जो अधिक तेजी से फैलने वाला है। लोगों के सिर पर एक अंजाना खतरा मंडरा रहा है। इसके बाद भी जिम्मेदारों का ध्यान नहीं है। नवीन बाजार क्षेत्र अंतर्गत 6 व्यक्ति रैपिड किट से जांच किए गए हैं। 2 व्यक्ति का ट्रैवल हिस्ट्री पाया गया,एक रायपुर व दूसरा जगदलपुर गए हुए थे। पुष्टि के लिए सैंपल भेजा गया है। प्रथम दृष्टया डेंगू जैसी स्थिति परिलक्षित हो रही है।

पांडातराई नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव टला

नई तिथि के साथ होगा वोटिंग

कवर्धा। पांडातराई नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का फिर से टल गया। एक नियम के तहत इसमें त्रुटि कर दी गई, जिसके कारण अध्यक्ष को मौका मिला और उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। इसके चलते अविश्वास प्रस्ताव को लेकर 13 अक्टूबर को होने वाला वोटिंग नहीं हो सका। बहुचर्चित बहुप्रतीक्षित नगर पंचायत पांडातराई के अध्यक्ष फिरोज खान के विरुद्ध मतदान उच्च न्यायालय के आदेश से स्थगित कलेक्टर कबीरधाम को फिर से नया तिथि तय कर अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान करने का आदेश दिया है।

कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन करने के कारण मतदान स्थगित किया गया। कलेक्टर द्वारा 3 अक्टूबर 2023 के आदेश को निरस्त किया गया क्योंकि वह कानूनी दृष्टिकोण से दोषपूर्ण था। नगर पंचायत अधिनियम में अनिवार्य नियम है कि मतदान तिथि के 10 पूर्ण दिन पूर्व की सूचना पत्र जारी किया जाए परंतु उक्त नियम का पालन नहीं किया गया। सूचना से वोटिंग समय 10 दिन हो रहा था जिसके कारण स्थगत आदेश मिल गया।

दूसरी ओर पार्षद भी हाईकोर्ट पहुंच गए। इस पर उच्च न्यायालय ने त्रुटि पूर्ण माना जो आदेश कलेक्टर द्वारा जारी किया गया। इसके चलते हाईकोर्ट से कलेक्टर कबीरधाम को नया दिनांक फि क्स करने का शीघ्र से शीघ्र आदेश दिया गया। हाईकोर्ट पहुंचा मामला 4 माह पूर्व नगर पंचायत पांडातराई अध्यक्ष के विरुद्ध 12 पार्षदों द्वारा दो अविश्वास प्रस्ताव आवेदन न्यायालय कलेक्टर कबीरधाम के यहां प्रस्तुत किया गया।

26 सितंबर 2023 निर्देश से कलेक्टर कबीरधाम द्वारा 3 अक्टूबर 2023 को अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान की तिथि तय की गई कि 13 अक्टूबर 2023 को मतदान कराया जाए। 13 अक्टूबर को मतदान होना था लेकिन नगर पंचायत अध्यक्ष फिरोज खान द्वारा विश्वास प्रस्ताव पर रीड पिटीशन द्वारा स्थगन आदेश की मांग की गई, आदेश निरस्त की गई।

पूर्व कांग्रेस विधायक योगेश्वर राज सिंह को पार्टी ने 6 साल के लिए किया निष्कासित

कवर्धा। कवर्धा विधानसभा के पूर्व विधायक राजपरिवार के सदस्य योगेश्वर राज सिंह को कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया गया है। उनके ऊपर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने का आरोप लगाते हुए 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है।

योगेश्वर राज सिंह को कांग्रेस के टिकट पर वर्ष 1998 व 2003 में दो बार विधायक चुने गए थे, जिन्होंने भाजपा के डॉ.रमन सिंह को भी हराया था। वर्ष 2008 में हार के बाद उनके सितारे गर्दिश में चले गए, जिसके बाद पार्टी में निष्क्रियता के चलते वापसी नहीं हो सकी। उनके मां व पिता भी कांग्रेसी विधायक रहे। कांग्रेस से कोई तवज्जों न मिलने के चलते वे पार्टी से दूर हो गए। वर्ष 2008 का चुनाव हारने के बाद कांग्रेस के किसी भी गतिविधि में वे शामिल नहीं रहे न ही सक्रियता दिखाई। पांच साल बाद वे सीधे 2013 में विधायक का टिकट मांगने के लिए राजमहल से बाहर निकले। टिकट नहीं मिली, पार्टी ने मोहम्मद अकबर को टिकट दे दिया, जिसके बाद वे फि र राजमहल से बाहर ही नहीं निकले।

इसके बाद 2018 के विधानसभा चुनाव में टिकट की मांग की, नहीं मिला। निर्दलीय चुनाव लड़ने फ ार्म भरा, तो उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के मान मनौव्वल के बाद वे अपना नामांकन वापस ले लिए थे। लेकिन उनकी पत्नी निर्दलीय चुनाव लड़ी। हांलाकि बाद में राहुल गांधी से मिलने के बाद उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार मोहम्मद अकबर को अपना समर्थन देने का ऐलान किया था। तभी से जिले में कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों खासकर मोहम्मद अकबर से राजपरिवार के संबंध बिगड़ते चले गए।

आप प्रत्याशी के लिए किया प्रचार-प्रसार

दरअसल हाल ही के चुनाव में उनके चचेरे भाई खड़गराज सिंह आम आदमी पार्टी से विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी हैं जिनके प्रचार के लिए योगेश्वर राज सिंह गए थे। इसी के चलते पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया है। हांलाकि ये तो सिर्फ एक बहाना माना जा रहा है। कांग्रेस पार्टी को अवसर मिल गया, नहीं तो वैसे भी योगेश्वर राज सिंह की कोई पूछ परख नहीं हो रही थी।

लगातार होती रही उपेक्षा, इसलिए रही नाराजगी

योगेश्वर राज सिंह को पांच साल कांग्रेस ने कभी याद नहीं किया। हाल ही में जब चुनाव प्रचार के लिए राहुल गांधी कवर्धा आए थे, तो पार्टी ने उन्हें बुलाया नहीं था। पूछ परख ना होने के चलते उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को नाराजगी भरा लेटर भी लिखा। लोगों में उसी समय चर्चा थी कि वे पार्टी से इस्तीफा देकर ससम्मान दूर हो जाते तो शायद अच्छा था। लेकिन वे पार्टी से इस्तीफ ा नहीं दिए, जैसे ही 7 नवंबर को मतदान हुआ, देर रात तक पार्टी ने उनके निष्कासन का लेटर जारी कर दिया।

अंबिकापुर के संजय पार्क में वन्य प्राणियों को गोद लेने की योजना सिर्फ बोर्ड में ही हो रही सुशोभित

अंबिकापुर। शहर के संजय पार्क में वर्ष 2012-13 में शुरू की गई वन्यप्राणियों को गोद लेने की योजना पूरी तरह से फेल हो गई है। वन प्रबंधन समिति ने वन्यप्राणियों से मानव समुदाय का लगाव हो, इसके लिए इन्हें गोद देने की पहल की थी। इस योजना को शुरू हुए एक दशक बीत रहे हैं, ऐसा कोई ऐसा व्यक्ति या समाज सेवी संगठन सामने नहीं आया है जो किसी वन्यप्राणी को गोद लेकर उसके खाने-पीने में होने वाले व्यय को नियमित वहन करे।

अंबिकापुर। शहर के संजय पार्क में वर्ष 2012-13 में शुरू की गई वन्यप्राणियों को गोद लेने की योजना पूरी तरह से फेल हो गई है। वन प्रबंधन समिति ने वन्यप्राणियों से मानव समुदाय का लगाव हो, इसके लिए इन्हें गोद देने की पहल की थी। इस योजना को शुरू हुए एक दशक बीत रहे हैं, ऐसा कोई ऐसा व्यक्ति या समाज सेवी संगठन सामने नहीं आया है जो किसी वन्यप्राणी को गोद लेकर उसके खाने-पीने में होने वाले व्यय को नियमित वहन करे। पीपुल्स फॉर एनीमल के सदस्यों ने पूर्व में वन्यप्राणियों को गोद लेने में रूचि दिखाई थी जो नियमित नहीं रही। योजना के प्रचार-प्रसार की ओर ध्यान नहीं देने से ऐसे हालात निरंतर सामने आ रहे हैं।

छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग के अधीन संजय पार्क में नगरवासियों के स्वस्थ्य मनोरंजन व परिवार के साथ पहुंचने वाले लोगों को बेहतर वातावरण प्रदान करने व्यवस्थाओं में बढ़ोतरी की गई है। यहां रोजाना योगासन के लिए भी शहर के लोग पहुंचते हैं। पार्क में बच्चों के लिए झूले, चिल्ड्रन ट्रेन सहित कई मनोरंजन की सामग्रियां हैं, लेकिन मेंटनेंस के अभाव में दम तोडने जैसी स्थिति बन रही है। दरअसल वन प्रबंधन समिति शंकरघाट वर्ष 2000 से पार्क के रखरखाव पर विशेष नजर रख रहा है। पार्क में स्वच्छ माहौल हो इसके लिए समिति की ओर से डेढ़ दर्जन कर्मचारी रखे गए हैं।

वर्ष 2012-13 से पार्क में रखे जाने वाले पशु-पक्षियों को गोद देने की परिपाटी वन प्रबंधन समिति शंकरघाट ने ही शुरू की है। इसके तहत संबंधित पशु-पक्षी को निर्धारित मासिक खर्च देकर कोई भी व्यक्ति गोद ले सकता है। विडंबना ही कहा जाए वर्ष 2015 में महावीर वार्ड के पीएन सिंह और वर्ष 2016 के नवंबर माह में सीतापुर की अनुराग बाई ने चीतल को गोद लेकर एक माह में इन पर होने वाले खर्च के लिए पांच-पांच सौ रुपए जमा कराए थे।

इसके बाद मानव समुदाय के लिए आकर्षण का केंद्र बने रहने वाले हिरण, कोटरा, खरगोशए,मोर सहित अन्य पशु-पक्षियों को गोद लेने कोई आगे नहीं आया। पीपुल्स फॉर एनीमल्स के सदस्यों ने यहां पलने-बढने वाले वन्यप्राणियों को गोद लेने रूचि जरूर दिखाई पर नियमितता नहीं बन पाई। ऐसे में पार्क के वन जीवों को गोद देने की मंशा धरी रह गई। वन प्रबंधन समिति व पार्क प्रभारी का कहना है कि वे यहां आने वाले संपन्न लोगों से पशु-पक्षियों को गोद लेने का आग्रह करते हैं।

इनके द्वारा हामी जरूर भरी जाती है पर कोई भी स्वविवेक से वन्य जीवों के आहार में होने वाले व्यय में सहभागी बनने सामने नहीं आता है। ऐसे में इनके आहार का प्रबंध सहित मूलभूत रखरखाव व कर्मचारियों का मनरेगा जॉब दर से भुगतान पार्क में आने-जाने वाले लोगों के द्वारा दिए जाने शुल्क से किया जाता है।

चीतल-कोटरा के साथ नीलगाय भी

बड़े सिंगों के साथ संजय पार्क में आने वालों को टकटकी लगाए देखते चीतलों का नामकरण वन विभाग की ओर से किया गया है। चंपा, लेदरी, दिलहरन, मनहरन, ढेला, सोनम, दुर्गा, चमेली, रामू आदि नामों से पुकारे जाने वाले चीतलों की उछलकूद होते रहती है। इनके साथ बाड़े में जंगल से भटककर आई एक नीलगाय भी रहती है। समिति के अध्यक्ष कहते हैं कि नीलगाय का जोड़ा होता तो इनकी संख्या में बढ़ती और ये यहां आने वालों के लिए आकर्षण का केंद्र होते।

65 कोटरा-कोटरी का विस्थापन

संजय पार्क में रहने वाले कोटरा-कोटरी की संख्या में अच्छी वृद्धि हुई थी। बाड़े में जगह की पड़ती कमी और इनकी बढ़ती संख्या को देखते हुए उच्च स्तर से मिली विभागीय अनुमति के बाद लगभग 65 कोटरा-कोटरी का विस्थापन इसी वर्ष कोरिया जिला के गुरुघासीदास उद्यान में किया गया है।

वर्तमान में यहां पांच कोटरा व 15 नर-मादा हिरण हैं। इसके अलावा कलर बड्र्स, गिनी पिग, उल्लू, खरगोश व डेढ़ दर्जन से अधिक मोर यहां आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। यहां के पशु-पक्षियों की समय-समय पर पशु चिकित्सक स्वास्थ्य जांच भी करते हैं। चिकित्सक के परामर्श के अनुसार इन्हें जरूरी दवाएं और टॉनिक दिया जाता है।

बलौदाबाजार कलेक्टर को निर्वाचन आयोग की नोटिस

बलौदाबाजार। रायपुर संभाग कमिश्नर ने कलेक्टर बलौदाबाजार चंदन कुमार को गुरुवार को नोटिस जारी किया है और नोटिस में धारा 151 के तहत गिरफ्तार भाजपा कार्यकर्ता को रिहा करने का निर्देश दिया है। इस आशय का आदेश उपायुक्त रायपुर संभाग के हस्ताक्षर से जारी हुआ। उक्त आदेश में नोटिस पर तत्काल प्रतिवेदन भी मंगाया गया है।

जारी आदेश में भाजपा निर्वाचन आयोग संपर्क समिति के संयोजक डॉ. विजय शंकर मिश्रा द्वारा गत दिनों भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय रायपुर को दी गई। शिकायत का उल्लेख है जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कलेक्टर चंदन कुमार ने धारा 151 के तहत प्राप्त शक्तियों और पद का दुरुपयोग किया है। साथ ही भाजपा के प्रचार को रोकने की कोशिश की है।

डॉ. मिश्रा ने अपनी शिकायत में उल्लेख किया था कि कलेक्टर चंदन कुमार द्वारा बलौदा बाजार में लगातार भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ चुनाव प्रचार को रोकने के उद्देश्य से किया कार्य किया जा रहा है। उन्होंने धारा 151 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत गिरफ्तार कर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की, भाजपा की प्रचार सामग्री जब्त की, जबकि भाजपा कार्यकर्ताओं ने कोई संज्ञान अपराध नहीं किया। फिर भी इसके खिलाफ धारा 151 दंड प्रक्रिया सहिता के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किया जाना विधि विरुद्ध है।

उन्होंने बताया था कि धारा 151 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत प्राप्त क्षेत्राधिकार केवल संज्ञान अपराध की भावना की स्थिति तक सीमित है। इस शिकायत को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने गंभीरता से लिया और रायपुर संभाग आयुक्त को भेजो इसके बाद कलेक्टर को नोटिस जारी कर भाजपा कार्यकर्ताओं को रिहा करने का निर्देश दिया गया है।

जिले में 75 फीसदी से अधिक मतदान

बलौदाबाजार-भाटापारा। विधानसभा निर्वाचन 2023 में बलौदाबाजार भाटापारा जिले के मतदाताओं में मतदान के लिए अभूतपूर्व उल्लास एवं उत्साह रहा। मतदान की प्रकिया पूर्ण करने के पश्चात मतदान दलों की वापसी पूरी हो गई है। जिस स्थान से मतदान सामग्री का वितरण किया गया था, उसी स्थान पर मतदान सामग्री की वापसी शनिवार को सुबह 4 बजे तक पूरी हो गई है। मशीनों के जमा करने के साथ ही स्ट्रांग रूम में सीलिंग की प्रक्रिया भी सुबह लगभग 11 बजे पूरी कर ली गई है। इस दौरान सभी आब्जर्वर,सभी प्रत्याशी एवं उनके प्रतिनिधिगण सहित रिटर्निंग अधिकारी उपस्थित रहे।

जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त अंतिम आंकड़े अनुसार जिले के चारो विधानसभा क्षेत्र के 8 लाख 94 हजार 582 मतदाताओं में से 6 लाख 72 हजार 544 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। जिसमें 3 लाख 38 हजार 758 पुरुष, 3 लाख33 हजार 775 महिला एवं 11 अन्य शामिल है।

जो डाले गए मतों में पुरूष मतदाता 75.71 प्रतिशत एवं महिला मतदाता 74.65 प्रतिशत है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 44 कसडोल में 2 लाख 69 हजार 969 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जो डाले गए मतों का 74.65 प्रतिशत है। इसमें 1 लाख 36 हज़ार 44 पुरूष मतदाता एवं 1 लाख33 हजार 923 महिला मतदाताओं ने मतदान किया,जो डाले गए मतों में पुरूष मतदाता 75.04प्रतिशत एवं महिला मतदाता 74.26 प्रतिशत है।

कलेक्टर-एसपी ने लाइन में लगकर किया मतदान

बलौदाबाजार। कलेक्टर चंदन कुमार अपने पत्नी अंकिता सुमन के साथ सुबह जिला मुख्यालय स्थित मतदान केंद्र क्रमांक 119 स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम पं. चक्रपाणि शुक्ल स्कूल पहुंचकर मताधिकार का प्रयोग किया। इस मौके पर कलेक्टर ने सहज सरल लाइन में लगकर अपने बारी का इंतजार किया। इस दौरान उन्होंने आम नागरिकों एवं ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों से मुलाकात कर व्यवस्थाओं के बारे भी जायजा लिया। वोट देने के पश्चात बनाएं गए आकर्षक सेल्फी जोन में आकर अपने फोटो लिए। कलेक्टर को अपने बीच देखकर मतदान करने आएं फर्स्ट टाइम वोटर ने भी सेल्फी लिए।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दीपक झा ने भी सुबह जिला मुख्यालय स्थित मतदान केंद्र क्रमांक 119 स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम पंडित चक्रपाणि शुक्ल स्कूल में ही पहुंचकर मताधिकार का प्रयोग किया। उन्होंने भी सभी जिला वासियों से अपने मताधिकार का प्रयोग कर देश के विकास में सक्रिय भूमिका निभाने की बात की है।

कलेक्टर के नेतृत्व में की गई निर्वाचन व्यवस्थाओं की हुई तारीफ

सरसीवां-बिलाईगढ़। विधानसभा निर्वाचन 2023 अंतर्गत सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिला प्रशासन द्वारा जिले के मतदान केंद्रों में मतदान तिथि 17 नवंबर 2023 के लिए की गई बेहतरीन व्यवस्थाओं की सराहना मतदान कर्मियों के अलावा मतदाताओं ने भी की है।

मतदान कराने हेतु मतदान केन्द्रों में पहुंचे मतदान दलों के सदस्यों ने मतदान केंद्रों में उपलब्ध कराई गई सुविधाओं पर संतोष एवं प्रसन्नता व्यक्त की है। साथ ही संगवारी मतदान केन्द्रों में दिव्यांगों एवं वृध्दजनों के लिए की गई व्यवस्था को सभी लोगों ने सराहा है। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. फरिहा आलम सिद्दीकी के निर्देशानुसार जिला प्रशासन ने इस विधानसभा निर्वाचन में मतदान केन्द्रों में मतदान दलों तथा सुगमतापूर्वक मतदान कराने हेतु साफ सफाई, बिजली, पेयजल, फर्नीचर, मतदान दलों के सोने तथा भोजन आदि की समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई है। इसके अलावा मतदान केंद्रों में मतदान करने पहुँचे आम नागरिकों ने भी सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के आदर्श मतदान केंद्रों की व्यवस्थाओं की मुक्तकंठ से सराहना की है।

पंचायत सचिव के खिलाफ शिकायत

लवन। पंचायत सचिव द्वारा कसडोल विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी के आभार मैसेज को अपने मोबाइल के व्हाट्सएप स्टेट्स पर लगाने का मामला सामने आया है। कांग्रेस प्रत्याशी संदीप साहू व कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से कारवाई की मांग की है। कलेक्टर चन्दन कुमार ने बताया कि जाँच के बाद कारवाई होगी।

आरोप है कि कसडोल विस के भाजपा प्रत्याशी धनीराम धीवर के द्वारा जारी किए गए आभार एवं धन्यवाद मैसेज को ग्राम पंचायत सकरी में पदस्थ कोलिहा (लवन)निवासी हरिकिशन वर्मा द्वारा अपने मोबाइल के व्हाट्सएप स्टेट्स पर लगाकर दिखा रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी संदीप साहू व कार्यकर्ताओं ने कारवाई करने की मांग कलेक्टर सहित राज्य चुनाव आयोग से की है, वहीं हरिकिशन वर्मा ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार बताया है।

अब छत्तीसगढ़ पुलिस करेगी झीरम हमले की जांच

नई दिल्ली। झीरम नक्सल हमले की जांच पर एनआईए की अपील को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. इसके साथ ही मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए जांच का रास्ता खुल गया है. जितेंद्र मुदलियार ने नक्सल हमले में षड्यंत्र की जांच करने एफआईआर दर्ज कराया था. एनआईए ने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर कहा था कि छत्तीसगढ़ पुलिस जांच नहीं कर सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई कर एनआईए की अपील को ख़ारिज कर दिया. सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव ने कहा कि शीर्ष न्यायालय के फ़ैसले के बाद अब छत्तीसगढ़ पुलिस षड्यंत्र के एंगल की जांच कर सकती है.

कलेक्टर वर्मा ने धान उपार्जन केन्द्र भोरमपुर कला का किया निरीक्षण

खैरागढ़। कलेक्टर गोपाल वर्मा ने जिले के धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण किया। उपार्जन केंद्र भोरमपुर कला में किसानों से बातचीत की और विभागीय अधिकारियों व समिति प्रबंधक को आवश्यक निर्देश दिए।

कलेक्टर गोपाल वर्मा ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि उपार्जन केन्द्रों में धान खरीदी कार्य सुचारू रूप से संचालित करें। इस दौरान समिति प्रबंधक महेश कुमार वर्मा को खरीदे गए धान के बोरे के स्टैक को भौतिक सत्यापन के योग्य व्यवस्थित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर गोपाल वर्मा ने आज धान खरीदी केंद्र में धान बेचने आए जोराताई के किसान बिसाहू राम वर्मा से चर्चा कर धान ऊपज और बिक्री से संबंधित जानकारी प्राप्त की। उन्होंने किसानों से धान बेचने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि धान खरीदी में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

इस वर्ष जिले में 39 समितियों के 51 उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी किया जा रहा है। गुरुवार की स्थिति में सभी धान उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी कार्य किया गया। शासन द्वारा इस वर्ष जिले हेतु 40 लाख क्विंटल धान खरीदी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्राप्त विभागीय जानकारी के अनुसार अभी तक कुल 2 लाख 63 हजार क्विंटल धान खरीदी कर लिया गया है। जिसके अंतर्गत मोटा धान 63 हजार क्विंटल, पतला धान 1 लाख 72 हजार क्विंटल, सरना धान 26 हजार 96 क्विंटल खरीदी कर ली गयी है। निरीक्षण के दौरान खाद्य उपर कलेक्टर डीएस राजपूत, जिला खाद्य अधिकारी भुनेश्वर चेलक, फूड इंस्पेक्टर विनोद सागर, डॉ. मकसूद, समिति प्रबंधक महेश वर्मा, उमेश वर्मा सहित समिति के स्टॉफ और किसान उपस्थित थे।

संगोष्ठी में गिनाई मुनगा की पत्तियों की खासियत

गंडई। अराकाजू ब्राजील में 8 से 11 नवंबर तक मुनगा पर तृतीय अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई। इसमें रानी अवंतीबाई लोधी कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र छुईखदान में कार्यरत सब्जी विज्ञान के सह प्राध्यापक डॉ. बीएस असाटी ने मुनगा पर दो शोध पत्र प्रस्तुत किए।

डॉ. असाटी गत 12 वर्षों से मुनगा पर अनुसंधान कर रहे हैं। इस संगोष्ठी में दूसरा प्रस्तुतिकरण डॉ. असाटी द्वारा मुनगा पत्तियों की अधिकतम उपज और बेहतर गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए रोपण ज्यामिति के प्रभाव का अध्ययन के बारे में किया गया। सम्मेलन में चीन, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, आर्मेनिया, फिलीपींस, ब्राजील, मिस्र आदि देशों से आए वैज्ञानिकों ने इसकी सराहना की।

डॉ. असाटी ने बताया कि मुनगे की पत्तियों में पाए जाने वाले क्रेरसेटिन और क्लोरोजेनिक एसिड से ब्लड शर्करा को नियंत्रित किया जा सकता है। यह चाय इंसुलिन को कंट्रोल करने में भी मददगार है। इसके अलावा इसमें फिनॉल कंटेंट, एंटीऑक्सीडेंट, फ्लेवोनॉयड्स, टेनन, बीटाकरोटिन, कैल्शियम आदि तत्व पाए जाते हैं। यह सभी मिलकर एक पॉवरफुल इम्युनिटी सिस्टम बनाते हैं, जो बॉडी के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। प्रतिदिन मोरिंगा चाय पीने से ताजगी और स्फूर्ति, ब्लड प्रेशर कंट्रोल, बेहतर पाचन तंत्र, त्वचा में निखार एवं चर्बी कम होती है।

मुनगा की खेती के प्रति जागरूकता लाने प्रतिवर्ष 14 सितम्बर को अंतरराष्ट्रीय मुनगा दिवस मनाने की शुरूआत हुई है। इसका उद्देश्य लोगों एवं किसानों के प्रति मुनगा की उपयोगिता, महत्व एवं उन्नत खेती का प्रचार-प्रसार करना है। जिससे किसान गुणवत्ता उत्पादन के साथ-साथ मार्केटिंग एवं प्रस्संकरण की जानकारी प्राप्त कर सके।

इस दिवस के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य के ग्राम नवागांव, भरेंगांव, धामनसरा, ढोलपिट्ठा, नाथूनवांगांव एवं मोहड़ में मुनगा की उन्नत किस्मों के हजारों की संख्या में पौधे लगवाकर एवं तकनीक का फैलाव कर मुनगा गांव विकसित किया है।

जेल में लगाई लोक अदालत, एक प्रकरण निराकृत

खैरागढ़। उप जेल खैरागढ़ में जेल लोक अदालत का आयोजन किया गया। एडीजे और जेएमएफसी के समक्ष कम संगीन अपराधों में शामिल अपराधियों को पेश किया गया।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के और अध्यक्ष आलोक कुमार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव के निर्देशानुसार उप जेल खैरागढ़ में 5 नवंबर को राज्य स्तरीय जेल लोक अदालत का आयोजन हुआ जिसमें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चन्द्र कुमार कश्यप और गुरु प्रसाद देवांगन जेएमएफसी खैरागढ़, जेल में उपस्थित हुए एवं छ.ग. उच्च न्यायालय द्वारा संचालित निर्देशानुसार जेल में लोक अदालत का आयोजन किया गया, उपरोक्त न्यायालय के समक्ष कम संगीन अपराधों में शामिल अपराधियों को पेश किया गया। जिसमें से 1 मुकदमे का मौके पर ही निपटारा किया गया।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चन्द्र कुमार कश्यप ने विचाराधीन बंदियों को संबोधित करते हुए कहा कि जो बंदी अपने वेयर से अधिवक्ता नियुक्त करने में सामर्थ नहीं हैं वह अपना एक आवेदन ताल्लुक विधिक सेवा समिति में द्वारा द्वारा जेल अधीक्षक के माध्यम से समिति में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं जहां से आप को आप के केस में पैरवी करने हेतु अधिवक्ता निशुल्क नियुक्त किया जाता है।

साथ ही ई कोर्ट एप के संबंध में बताया कि ई कोर्ट एप के माध्यम से आप अपने कैसे की जानकारी कहीं भी और कभी भी जान सकते हैं। आगे अध्यक्ष /न्यायाधीश तालुकाधिक सेवा समिति खैरागढ़ द्वारा विचाराधीन बंदियों का हालचाल पूछा गया और उनके स्वास्थ्य के बारे में भी जाना गया साथ ही उनकी समस्याओं को भी सुना गया और रहने स्वास्थ्य केंद्र एवं पाकशाला का निरीक्षण किया गया और पूरे जेल का भी भ्रमण किया। और यहां की व्यवस्था को और सुव्यवस्थित और सुदृढ़ करने के लिए सुझाव और दिशानिर्देश दिए ।

उक्त जेल लोक अदालत में पैरालीगल वालंटियर गोलूदास साहू, प्रसन्न श्रीवास्तव, ,जेल अधीक्षक योगेश कुमार बंजारे उप जेल खैरागढ़, एवं सिपाही यशवंत कुमार नायक, प्रेम सागर साहू, प्रकाश कुर्रे,चुरामन प्रसाद कुर्रे, सोहन साहू उपस्थित रहे।

सेल्फी जोन बना मतदाताओं के लिए विशेष आकर्षण का केन्द्र

सरसीवां-बिलाईगढ़। जिले के सारंगढ़ और बिलाईगढ़ विधानसभा में कुल 24 आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों में विशेषतौर पर सजावट की गई है। सेल्फी पॉइंट पर लोग मतदान देकर युवाओं से लेकर बुजुर्ग सभी सेल्फी जोन में अपनी तस्वीर कैद कर रहे थे, और इस बार किए गये मतदान को यादगार बना रहे हैं। कई आदर्श मतदान केंद्रों को फूलमाला से सजाया गया है, जो लोगों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है।

इसी तरह यहां मतदाता मित्र भी वरिष्ठजनों का और दिव्यांग मतदाताओं का भरपूर सहयोग कर रहे हैं। कई स्थानों पर तिलक और आरती लगाकर भी मतदाताओं का स्वागत किया जा रहा है।

सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में 87 हजार से अधिक किसान पंजीकृत

सारंगढ़। जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ के कलेक्टर डॉ. सिद्दकी के निर्देश पर 1 नवंबर से धान खरीदी प्रारंभ हुई थी। इस विषय को लेकर जब खाद्य कलेक्टर चित्रकांत ध्रुव से चर्चा हुई तो उन्होंने प्रेस को बताया कि -जिले के सारंगढ़ , बरमकेला , बिलाईगढ़ तीनों विकासखंड में 65 सहकारी समितियां है। जिनके उपार्जन केंद्र 86 है , इन धान खरीदी केंद्रों में शासन द्वारा सत्र 2023 - 2024 के लिए खरीदी लक्ष्य 399837 (में.टन) धान खरीदी का लक्ष्य है, पंजीकृत किसानों की कुल संख्या 87 121 है , जिनमें से दिनांक 19 नवंबर की स्थिति में 801 किसानों ने धान विक्रय किया, शेष किसानों की संख्या 86220 है। धान विक्रय प्रक्रिया को पारदर्शीय बनाने के लिए 2260 टोकन धान विक्रय क्रेंद्र हेतु काटे गये थे , जबकि 2206 टोकन में ही धान खरीदी कार्य संपन्न हुआ है । धान खरीदी केंद्रों में मोटा , पतला , सरना तीन किस्म की धान खरीदी की जाएगी । 19 नवंबर की स्थिति में मोटा धान 4703 . 92 क्वि. वहीं पतला धान की बोहनी नहीं हुई है। सरना 372 . 36 क्विंटल धान की खरीदी की गई है। अभी तक खरीदी गई धान की स्थिति यह है कि - 5076.28 क्विंटल धान की खरीदी हुई है।

खाद्य कलेक्टर चित्रकांत ध्रुव ने बताया कि 64 राइस मिलों के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें एक राइस मिल का पंजीयन हुआ है, लेकिन धरोहर राशि जमा न होने की स्थिति में डीओ जारी नहीं किया गया है। मिलर्स द्वारा उठाए गए धान की मात्रा निरंक है । वर्तमान में उपार्जन केंद्र में 5076 28 क्विंटल धान संग्रहित है।

पूर्व लिखित अनुमति के बिना ध्वनि विस्तारक यंत्र प्रतिबंधित

सारंगढ़-बिलाईगढ़ । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. फरिहा आलम सिद्दीकी ने रोगियों, वृद्धाओं, दिव्यांगजनों, विद्यार्थियों की पढ़ाई आदि की बाधा एवं परित्रास तथा लोक परिशांति को ध्यान में रखते हुए जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ की सीमा के अंतर्गत पूर्व लिखित अनुमति के बिना ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग आगामी आदेश तक तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया है।

इस आशय का आदेश 07 नवंबर 2023 को जारी किया गया है। उच्चतम न्यायालय तथा छत्तीसगढ़ शासन के आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा दिए गए निर्देश के अनुपालन में ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने एवं मल्टीटोन हॉर्न-प्रेशर हॉर्न के साथ-साथ डीजे के विरूद्ध जब्तीकरण की कार्रवाई किए जाने तथा सम्यक जांच के लिए अधिकारियों की दल गठित की गई है। गठित दल अपने-अपने थाना क्षेत्र में आवश्यक कार्रवाई करेंगे। कोई भी नागरिक इन दलों से संपर्क कर शिकायत कर सकता है।

जिले में हो रहा आयुष्मान भारत योजना का सफल क्रियान्वयन

सारंगढ़। जिला कलेक्टर डॉ. सिद्दकी के निर्देशन व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधि. डॉ.एफआर निराला के मार्ग दर्शन में नए जिले सारंगढ़ बिलाईगढ़ के गठन के पश्चात आज की स्थिति में कुल राशनकार्ड हितग्राहियों 680022 में से कुल 508 445 कार्ड बने तथा बाकी 171577 हितग्राहियों का कार्ड बनना बचा है। इस प्रकार जिले भर से कुल 75 फीसदी जनसंख्या कवर किया जा चुका है। इसके तहत हितग्राही आवश्यकतानुसार स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं।

आयुष्मान भारत योजना अन्तर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पीएमजे एवाई या डॉ.खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना (डीकेबीएसएसवाई) तथा मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना (एमव्हीएस एसवाई) कुल दो प्रकार की हैं। जिसमें बीपीएल राशन कार्ड हितग्राही दोनों योजना से 5 - 25 लाख प्रति परिवार तक की स्वास्थ्य सहायता लाभ ले सकते हैं व एपीएल राशनकार्ड के हितग्राही को 50 हजार रुपए व मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना एमव्हीएस एसवाई का लाभ लेने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन पश्चात लाभ ले सकते हैं।

प्रदेश के इम्पैनल्ड अस्पतालों से ही हितग्राही आवश्यकतानुसार ईलाज करवा सकते हैं जहाँ विभिन्न बीमारियों के पैकेज के अनुसार राशि का आबंटन संबंधित अस्पताल को मरीज का ईलाज करने के एवज में किया जाता है। 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों का ईलाज माता पिता के आयुष्मान कार्ड से होता है। अगर किसी हितग्राही का राशन कार्ड नही बना है या राशनकार्ड से किसी कारण वश नाम कट गया है तो आवश्यक ईलाज के लिए राशनकार्ड में तत्काल नाम जोड़कर अस्पताल के आयुष्मान विभाग से कार्ड बनाया जाता है फिर मरीज आसानी से प्रदेश के उच्च संस्थानों से ईलाज करवा सकता है।

ऐसे ही एक धुता निवासी 25 वर्षीय सन्तोष एपिथेलियाइड हिमेंजियोमा से ग्रसित था, संयोगवश उसका राशनकार्ड से नाम भी अलग हो जाने के कारण आयुष्मान कार्ड नही बन पाने पर इलाज नहीं हो रहा था, कल ही आयुष्मान भारत के जिला नोडल डॉ. पीडी खरे को पता चलने पर तत्काल जिला खाद्य कलेक्टर सी के ध्रुव से सम्पर्क कर राशनकार्ड में नाम जोड़कर सिविल अस्पताल सारंगढ के आयुष्मान मित्र श्री हरिशंकर साहू के द्वारा आयुष्मान कार्ड बनाकर दे दिया गया। अब ईलाज के लिए प्रदेश के उच्च चिकित्सा संस्थान एम्स रायपुर जाएगा।

इस तरह से योजना का लाभ हितग्राहियों को तत्काल देने का प्रावधान है । जिससे अनावश्यक तकलीफ न हो और समय पर ईलाज हो सके। चिरायु टीम के डॉक्टरों द्वारा भी ऐसे बच्चे ईलाज हेतु चिन्हित किये जाते है जिनका राशनकार्ड में नाम नही रहता किंतु प्राथमिकता से उनका नाम जोड़कर निकटतम सिविल अस्पताल से आयुष्मान कार्ड बनाकर तत्काल लाभ दिया जाता है।

दस वर्ष पहले शासन ने सडक़ बनाने जमीन अधिग्रहण किया, नहीं मिला मुआवजा

अंबागढ़ चौकी। जमीन का मुआवजा नहीं मिलने से वह अपना इलाज नहीं करा पा रहा था। आखिरी सांसों तक वह सरकार से पैसा मिलने का इंतजार करता रहा, लेकिन उसे शासन-प्रशासन से न तो मुआवजा मिला और न ही किसी तरह की राहत मिल पाई। आखिरकार बुधवार को 75 वर्षीय सुखुराम ने पैसे के अभाव में दम तोड़ दिया। सुखुराम पेट से संबंधित बीमारियों से जूझ रहा था। इस घटना के बाद नगरवासियों में शासन-प्रशासन के खिलाफ भारी आक्रोश है।

जानकारी के अनुसार नगर के वार्ड 12 निवासी 75 वर्षीय सुखुराम निषाद की वर्ष 2014 में लगानी जमीन को शासन ने चौकी से पांगरी तक सडक़ बनाने के लिए अधिग्रहण कर लिया था, तब से सुखुराम अपनी जमीन का मुआवजा लेने अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों का चक्कर काट रहा था। सुखुराम को पिछली सरकार भाजपा के डॉ. रमन सिंह सरकार के समय भी मुआवजा नहीं मिला और कांग्रेस के भूपेश सरकार के पौने पास साल के कार्यकाल में भी मुआवजा नहीं मिल पाया। आखिरी सांसों तक मुआवजा के लिए कलेक्टरेट व एसडीएम कार्यालय का चक्कर काटता रहा।

सुखुराम सोमवार को भी जिला कार्यालय मोहला मानपुर अंबागढ चौकी के जिला मुख्यालय मोहला जाकर कलेक्टर व एसडीएम से मिला था। सुखुराम के साथ मोहला गए हेमंत बोरकर, सोहन निषाद, संतु निषाद, बुधकुंवर निषाद, उमा निषाद, झोला हल्वा ने बताया कि वे सोमवार को डीएम व एसडीएम से मिले थे। उनकी संख्या दस से अधिक थी। मुआवजा लेने के लिए भटक रहे इन किसानों ने बताया कि कलेक्टर ने उन्हे पखवाड़ेभर में मुआवजा मिल जाने का आश्वासन दिया था, लेकिन बुधवार को सुखुराम ने दम तोड़ दिया। किसानों ने बताया कि सुखुराम पिछले एक-दो वर्ष से तबियत खराब था। वह पेट संबंधी बीमारियों से जूझ रहा था। पैसे के अभाव में वह अपना इलाज नहीं करा पा रहा था। सुखुराम इस बात की राह देख रहा था कि मुआवजा मिलने के बाद वह किसी अच्छे हास्पिटल में अपना इलाज कराएगा, लेकिन इसी इंतजार में उसने दम तोड़ दिया। सुखुराम की हुई अचानक मौत व उसकी कहानी सुनकर नागरिकों में शासन एवं प्रशासन की कार्यप्रणाली को लेकर गहरा आक्रोश है।

चौकी के 20 किसानों की गई जमीन

पांगरी व चौकी के मध्य मुख्य सडक़ निर्माण के लिए अंबागढ़ चौकी नगर के 20 किसानों की जमीन गई है। इसमे निर्मल बोरकर पिता मानिकराम, राजेश पिता नारायण प्रसाद अग्रवाल, सदाराम पिता सखाराम बोरकर, इंद्रकुमार पिता संतराम रामटेके, नाजी सैयदा पति सफाकुद्दीन खान, सोहन लाल पिता बंशी, बैसाखिन बेवा बंशी, एजाज पिता आमिर खान, भुवनलाल- गोविंद लाल पिता तुलसी, जसवंता बेवा तुलसी, मयाराम पिता जयाराम कलार, जकतु पिता महंगु, केवट, किसन पिता मंहगु, बिसन पिता महंगु केवट, यशवंत-कमला-दुर्गा पिता कीर्तनलाल, अनुसुईया बेवा कीर्तन लाल, संतोष डेविड पिता विनोद कुमार, रूपकुवर बेवा विनोद मरार, मेघनाथ पिता भागवत, दशरथ पिता बरनू, चंमरूराम-गंगाराम-बिंदाबाई पिता झाडूराम केवट, इंदल पिता छत्तर केवट, बाबूलाल-भैयाराम-बिस्सुराम पिता बालाराम निषाद, बुधकुवर-तीजकुवर-आशाबाई-अनिशाबाई पिता बालाराम, जोरन बेवा बाला, सुखुराम पिता अमरू की जमीन शासन ने सडक़ बनाने के लिए अधिग्रहित किया था।

मोहला एसडीएम हेमेन्द्र भुआर्य ने बताया कि पांगरी सडक़ निर्माण के लिए जिन-जिन किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया गया है, उन्हें जल्द से जल्द मुआवजा प्रदान किया जाएगा। प्रशासनिक प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। राशि मिलने के बाद शीघ्र मुआवजा प्रदान किया जाएगा।

आचार संहिता के दौरान 1442 पर प्रतिबंधात्मक व 2319 चालकों पर कार्रवाई, साड़ियां व नगदी जब्त

बेमेतरा। जिले में पुलिस की कड़ाई और लगातार पेट्रोलिंग की वजह से चुनाव के दिन एक भी वाद-विवाद की एफआईआर दर्ज के लिए किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं मिली। आदर्श आचार संहिता के दौरान अब तक 779 प्रकरण में 1,442 लोगों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 2,319 वाहन चालकों के विरूद्ध चालानी कार्रवाई कर 9,86,200 रुपए वसूले गए। 142 वारंट की तामिली, 241.685 लीटर अवैध शराब कीमत करीबन 1.19 लाख रुपए, 14.191 किलोग्राम कीमती लगभग 2 लाख 700 रुपए और पुलिस व निर्वाचन टीमों द्वारा नकदी 8,64,400 रुपए एवं 69,67,742 रुपए की साड़ियां, वाहन व अन्य सामग्री जब्त की गईं।

केंद्रीय सुरक्षा बल व पुलिस की रही प्रमुख भूमिका

विधानसभा चुनाव संपन्न कराने में पुलिस कर्मियों और केन्द्रीय सुरक्षा फोर्स के जवानों एवं चुनाव कार्य में लगी टीम की प्रमुख भूमिका रही। आदर्श आचार संहिता के दौरान 1,442 लोगों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई हुई। निर्वाचन के एक दिन पूर्व तक असामाजिक तत्वों व गुंडा बदमाशों की कड़ी निगरानी की गई। आदर्श आचार संहिता के दौरान 142 वारंटी एवं इसके पूर्व माह जून से 506 वारंटियों सहित कुल 648 वारंटियों को ऑपरेश ईगल अभियान चलाकर प्रदेश के अलग-अलग जिलों और दूसरे प्रदेशों से भी लाकर न्यायालय में पेश किया गया। इस कार्रवाई का सीधा असर निवार्चन के दौरान देखने को मिला।

चेकपोस्ट पर जवानों की रही जबरदस्त चौकसी

विधानसभा चुनावों में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार अंतरजिला चेकपोस्ट के अलावा प्रमुख चौक-चौराहों पर निगरानी दल की तैनाती की गई थी। वहीं किसी संदिग्ध के मिलने पर उसकी वीडियोग्राफी कराई गई। इस दौरान लोगों को बेवजह परेशान नहीं किया गया। लेकिन किसी के पास कुछ भी मिलता तो उससे संबंधित बिल या फिर कागजात मांगे गए। नहीं दे पाने पर वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई। इसके चलते चुनाव का सफल संचालन किया गया।

एसपी ने भी कर्मियों का माना आभार

एसपी भावना गुप्ता ने जिले में विधानसभा चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष, शान्ति पूर्ण एवं पारदर्शिता के साथ मतदान के लिए सभी अधिकारी-कर्मचारियों, केन्द्रीय सुरक्षा बल के जवानों और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों एवं चुनाव कार्य में लगी टीमों का आभार माना। इसके साथ ही कलेक्टर पीएस एल्मा ने भी चुनाव के लिए तैनात सभी कर्मियों का आभार जताया है। बता दें कि 17 नवंबर को मतदान हो चुका है। अब 3 दिसंबर को चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे।

पुलिस की तत्परता से कहीं भी नहीं हुआ विवाद

पूरे जिले में चुनाव के दिन एक भी वाद-विवाद के प्रकरणों में चुनाव के दिन कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। लगातार पेट्रोलिंग और पुलिस टीम द्वारा शिकायत स्थल पर त्वरित पहुंचने से कहीं भी विवाद नहीं हुआ। 2023 में अब तक 967 प्रकरण में 989 व्यक्तियों से 1682 लीटर अवैध शराब कीमत लगभग 9,10,562 रुपए जब्त कर सैकड़ों अवैध कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई।

चुनाव के बाद अब प्रत्याशी कर रहे जीत-हार का आंकलन, नोटा को लेकर सभी में टेंशन

बेमेतरा। जिले के तीनों विधानसभा के लिए मतदान प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद अब साजा विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी रविन्द्र चौबे, भाजपा प्रत्याशी ईश्वर साहू, बेमेतरा विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी आशीष छाबड़ा, भाजपा प्रत्याशी दिपेश साहू व नवागढ़ विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी दयाल दास बघेल व कांग्रेस प्रत्याशी गुरू रूद्र कुमार के हार जीत का आंकलन का दौर शुरू हो गया है।

नामांकन दाखिल करने के बाद से प्रचार प्रसार व चुनावी प्रबंधन में जुटे रहे। अब जब मतदान की प्रकिया पूर्ण हो चुकी है तब सभी दावेदार व पार्टी कार्यकर्ता अब बूथवार आंकड़ा जुटा कर अपने-अपने संभावित मतों का आंकलन कर रहे हैं। जिले में तीनों विधानसभा में से नवागढ़ में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ओमप्रकाश बाचपेयी के संभावित मत को लेकर एक त्रिकोणीय स्थिति नजर आ रही है।

बेमेतरा में भाजपा प्रत्याशी दिपेश साहू, कांग्रेस प्रत्याशी आशीष छाबड़ा के मध्य ही माना जा रहा है। साजा में कांग्रेस प्रत्याशी रविन्द्र चौबे व भाजपा के ईश्वर साहू के बीच ही आमने-सामने की स्थिति है। जिले में दोनों राजनीतिक दल के प्रत्याशी समेत कुल 46 प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं। बेमेतरा विधानसभा में शिक्षक रहे अर्जुन सिंह ठाकुर व संजीव अग्रवाल का असर कुछ क्षेत्रों में दिखाई दिया है, जिसमें साजा में 14, बेमेतरा में 18 व नवागढ़ में 14 दावेदार मैदान में हैं।

नोटा में डाले जाने वाले मत भी हजारों में

बीते 2018 के निर्वाचन के दौरान साजा, बेमेतरा व नवागढ़ विधानसभा में हजारों की संख्या में मतदाताओं ने नोटा का बटन दबाया था, जिसे देखते हुए इस बार भी पूर्व की तरह नोटा बटन में मत डाले जाने की संभावना जताई जा रही है। जिले के तीनों विधानसभा के लिए मतदान प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद अब साजा विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी रविन्द्र चौबे, भाजपा प्रत्याशी ईश्वर साहू, बेमेतरा विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी आशीष छाबड़ा, भाजपा प्रत्याशी दिपेश साहू व नवागढ़ विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी दयाल दास बघेल व कांग्रेस प्रत्याशी गुरू रूद्र कुमार के हार जीत का आंकलन का दौर शुरू हो गया है।

मतदान कर्मचारी अव्यवस्था एवं भेदभाव के हुए शिकार, की शिकायत

मुंगेली। बेलतरा एवं कोटा विधानसभा क्षेत्र में निर्वाचन ड्यूटी में गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिल के मतदान दल कर्मचारियों को मूलभूत सुविधाओं की अनदेखी, अव्यवस्था एवं भेदभाव की शिकायत सोमवार को मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत निर्वाचन आयोग नईदिल्ली, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, रायपुर एवं कलेक्टर से कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा ने करते हुए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने एवं आगामी चुनावों में जिले के कर्मचारियों की निर्वाचन ड्यूटी जिले अंतर्गत लगाने की मांग की गई। कलेक्टर को सौंपे गए शिकायत पत्र में बताया कि जिले के कर्मचारियों की निर्वाचन ड्यूटी बेलतरा एवं कोटा विधानसभा क्षेत्र, जिला बिलासपुर में लगाई गई थी। मतदान दल को 16 नवंबर को मतदान केंद्रों में रवाना कर दिया गया था। जहां बेलतरा विधानसभा के बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत स्थित शहरी मतदान केंद्रों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव था। मतदान दल के लिए खाना और चाय-नाश्ता का भी कोई व्यवस्था नहीं की गई थी।

मतदान के लिए महिलाओं, बुजुर्गों, दिव्यांगों तथा युवाओं में दिखा उत्साह

मुंगेली। जिले में विधानसभा चुनाव में उत्सव का माहौल दिखा। मतदान में बुजुर्ग, दिव्यांग, महिलाओं सहित युवाओं नें भी बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। लोकतंत्र के चुनावी उत्सव में शामिल होने उत्साहित मतदाता, केन्द्रों पर सुबह से ही मतदान के लिए कतार लगा लिए थे। सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे के बाद केंद्र के अंदर आए मतदाताओं ने रात तक मतदान किए।

इस बार भी मतदान केन्द्रों में बुजुर्ग एवं दिव्यांग मतदाताओं के लिए व्हीलचेयर, रैम्प आदि की बेहतर व्यवस्था की गई थी। बुजुर्ग एवं दिव्यांगजनों के लिए एनसीसी के बच्चों ने मतदान मित्र के रूप में सहयोग किया तथा पुलिस के जवानों ने भी सेवा भावना के साथ मदद की। इस दौरान युवाओं ने भी उत्साह दिखाया।

महिलाओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा ली

मुंगेली विधानसभा क्रमांक 27 में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर मतदान करने पहुंची। लंबी कतार में लगकर अपनी बारी की प्रतीक्षा करती रही। ज्ञात हो चुनाव आयोग द्वारा महिलाओं को मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए आदर्श मतदान केंद्र को विशेष ढंग से सजाया गया था। केंद्रों में बैठने के लिए कुर्सी, टेबल, पानी, छाया, शौचालय की व्यवस्था भी की गई थी।

बुजुर्गों ने भी निभाई भागीदारी

मुंगेली जिले के ग्राम करही की बुजुर्ग महिला थानवरी यादव आदर्श मतदान केंद्र करही के केंद्र क्रमांक 119 में वोट डालने पहुंची। उन्होंने कहा कि पिछले 50 वर्षों से मतदान कर रही है। केन्द्र में रैम्प और व्हीलचेयर होने से वोट डालने में काफी सुविधा मिली है। 63 वर्षीय दिव्यांग मतदाता शेखर पात्रे ने व्हीलचेयर के सहारे स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में बनाए गए मतदान केंद्र में पहुंचकर मतदान किया। इसी प्रकार 80 वर्षीय प्रेमाबाई मतदान करने पहुंची। दिलचस्प बात यह है कि इनमें कई बुजुर्ग ठीक से चलने की स्थिति में नहीं थे, लेकिन मतदान केन्द्र में मिली सुविधाओं तथा दृढ़ इच्छाशक्ति ने वोट डालने के लिए प्रेरित किया। 83 वर्षीय बुजुर्ग फेरुराम साहू भी मतदान केन्द्र पहुंच कर मताधिकार के प्रयोग किए। बुजुर्गों का कहना है कि यह उनका कर्तव्य नहीं बल्कि उनका का धर्म है।

कुरूद विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी से भितरघात की आशंका

प्रदेश अध्यक्ष ने पांच नेताओं को जारी किया नोटिस

धमतरी। कुरूद विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की प्रत्याशी तारिणी नीलम चंद्राकर से भितरघात करने आशंका को देखते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कांग्रेस के पांच नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने जनपद पंचायत कुरूद की अध्यक्ष शारदा देवी साहू, नगर पंचायत कुरूद के अध्यक्ष तपन चंद्राकर, नगर पंचायत भखारा के पूर्व अध्यक्ष भरत नाहर व वर्ष 2018 में कुरूद की कांग्रेस प्रत्याशी रही लक्ष्मीकांता साहू, उनके पति हेमंत साहू को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

17 नवंबर को विधानसभा चुनाव का मतदान संपन्न होने के बाद प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने रायपुर में 18 को कांग्रेस के प्रत्याशियों की बैठक लेकर समीक्षा की। बैठक में पार्टी विरोधी गतिविधियों की शिकायत करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी तारिणी नीलम चंद्राकर ने भीतरघात की आशंका जताई। इसके बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने रविवार को इन पांचों नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी कर 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा है।

उल्लेखनीय है जनपद अध्यक्ष शारदा साहू, नगर पंचायत अध्यक्ष तपन चन्द्राकर, भरत नाहर व लक्ष्मीकांता साहू ने टिकट की मांग की थी। कांग्रेस ने तारिणी नीलम चंद्राकर को टिकट दे दिया। इसके बाद से पारिवारिक व स्वास्थ्यगत कारण बताकर अथवा दूसरे विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करने व कुरूद में पूछपरख नहीं होने की बात कहकर इन नेताओं ने कुरूद के चुनाव प्रचार अभियान से दूरी बना ली थी।

बगावत से जब्त हुई थी कांग्रेस की जमानत

वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में पूरे प्रदेश में लहर के बावजूद कुरूद में कांग्रेस तीसरे स्थान पर आई थी। वहीं जमानत जब्त हो गई थी। कांग्रेस से टिकट न मिलने पर बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले नीलम चंद्राकर दूसरे स्थान पर रहे थे। यहां से भाजपा के अजय चंद्राकर को जीत मिली थी। इसके बाद नीलम चंद्राकर को कांग्रेस ने निष्कासित कर दिया गया। बाद में उनकी पार्टी में वापसी हुई। उन्हें कुरूद मंडी का अध्यक्ष भी बना दिया गया। इतना ही नहीं इस बार के चुनाव में उनकी पत्नी तारिणी चंद्राकर को कांग्रेस ने टिकट दे दिया। लक्ष्मीकांता साहू टिकट वितरण से पूर्व लगातार बागी को टिकट नहीं देने की मांग उठाती रही।

धमतरी जिले की तीन सीटों पर 79.89% मतदान,

सबसे ज्यादा कुरुद में 82.6 प्रतिशत, 2018 से छह फीसदी कम वोटिंग

धमतरी। धमतरी जिले की तीनों विधानसभाओं में मतदाताओं में विधानसभा चुनाव के मतदान को लेकर अपार उत्साह रहा। लोगों के वोट से लोकतंत्र मजबूत हुआ। अंतिम आंकड़ों के अनुसार जिले में कुल 79.89 प्रतिशत मतदान हुआ है। शाम साढ़े सात बजे तक की स्थिति में तीनों विधानसभा के कुछ केंद्रों में मतदान जारी रहा। शाम पांच बजे तक केंद्रों में पहुंचे लोगों को वोट डालने का अवसर प्रदान किया गया। अंतिम समय में लाइन लंबी होने के कारण देर शाम तक मतदान होता रहा। मतदान का प्रतिशत अंतिम आंकड़े जारी होने पर और बढ़ने की उम्मीद है।

अंतिम आंकड़ों के अनुसार धमतरी जिले में 79.89 प्रतिशत मतदान हुआ। सिहावा विधानसभा में 78.20, कुरुद में 82.6 व धमतरी में 78.8 प्रतिशत मतदान हुआ हैं। देर शाम तक तीनों विधानसभाओं के मतदान केंद्रों में मतदान होता रहा।

वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में 84.59 प्रतिशत मतदाताओं ने धमतरी जिले में अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। धमतरी विधानसभा में 82.27 प्रतिशत, कुरुद में 88.83 प्रतिशत व सिहावा विधानसभा में 82.68 प्रतिशत मतदान हुआ था। वर्ष 2013 में धमतरी जिला में 84.64 प्रतिशत मतदान हुआ था। धमतरी में 83.49 प्रतिशत, कुरुद में 88.56 प्रतिशत एवं सिहावा विधानसभा क्षेत्र में 81.88 प्रतिशत लोगों ने मतदान केंद्र पहुंचकर वोट डाला था।

वर्ष 2013 का मतदान धमतरी जिला - 84.64 धमतरी- 83.49 कुरुद- 88.56 सिहावा- 81.88

वर्ष 2018 का मतदान धमतरी जिला- 84.59 धमतरी- 82.27 कुरुद- 88.83 सिहावा- 82.68

वर्ष 2023 का मतदान धमतरी जिला- 79.89 धमतरी- 78.8 कुरुद- 82.6 सिहावा- 78.201

नक्सलियों ने जन अदालत लगाकर युवक को उतारा मौत के घाट

बैनर जारी कर लगाया मुखबिरी करने का आरोप

कांकेर। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में नक्सलियों की कायराना करतूत सामने आई है। यहां नक्सलियों ने जन अदालत लगाकर युवक की हत्या कर दी। हत्या की जिम्मेदारी रावघाट एरिया कमेटी ने ली है। हत्या के बाद नक्सलियों ने मौके पर बैनर भी बांधा है, जिसमें हत्या की वजह भी लिखी है। मामला कोयलीबेड़ा क्षेत्र के ग्राम गोम्मे का है।

मिली जानकारी के अनुसार सोनपुर थाना अंतर्गत कांकेर व नारायणपुर जिले के बीच बसे ग्राम गोमे व गुंदुल से नक्सलियों ने सोमवार को तीन युवक अमर सिंह उइके, सुरजू आचला व एक अन्य युवक का अपहरण किया था। इनमें से अमर सिंह उइके की नक्सलियों ने आदनार के जंगलों में जनअदालत लगाकर हत्या कर दी। नक्सलियों ने बैनर में लिखा है कि ग्राम गोम्मे गांव का निवासी अमर सिंह उइका ने डीआरजी को हमारे साथियों के बारे में सूचना दी। जिसकी वजह से दो नक्सल साथी मारे गए। युवक की इस गलती पर उसे मौत की सजा दी गई है।

बता दें कि सोमवार को ही सुरक्षाबल के जवानों ने नक्सलियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम करते हुए पांच आईईडी बरामद किया था। सुरक्षाबलों को नुकसान पहुंचाने आईईडी प्लांट कर रखा था। सभी आईईडी को जवानों ने निष्क्रिय कर दिया।

कलेक्टर डॉ. प्रियंका शुक्ला, एसपी दिव्यांग पटेल ने डाला वोट

कांकेर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है। मतदान के लिए लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। पूर्व नक्सली कमांडर ने पहली अपने मतदान का प्रयोग किया। वहीं कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. प्रियंका शुक्ला, एसपी दिव्यांग पटेल और जिला पंचायत के सीईओ सुमित अग्रवाल ने आदर्श मतदान केंद्र माहुरबंदपारा में वोट दिया।

पूर्व नक्सली कमांडर नक्सली आतंकों से तंग आकर आत्मसमर्पण की थी। जिसके बाद छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में पहली बार पूर्व नक्सली कमांडर ने वोट डालकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया।

सप्ताह में सिर्फ दो दिन मंगलवार-गुरुवार को जगदलपुर से रायपुर जायेगी फ्लाइट

जगदलपुर। बस्तर जिला मुख्यालय से हवाई सेवा के लिए विंटर समयसारणी जारी किया गया है। अब सप्ताह में सिर्फ दो दिन ही एलायंस एयर की फ्लाइट जगदलपुर से रायपुर जा रही है। बाकी दिन फ्लाइट हैदराबाद से जगदलपुर आएगी लेकिन रायपुर नहीं जाएगी। शेड्यूल में बुधवार की सेवा पर ब्रेक भी लगाया गया है। इस दिन हैदराबाद से जगदलपुर फ्लाइट नहीं आएगी। इस तरह सप्ताह में 06 दिन फ्लाइट का संचालन होगा। जगदलपुर से बड़ी संख्या में यात्री रायपुर की यात्रा करते हैं, लेकिन जगदलपुर-रायपुर के फेरे घटने से उनमें निराशा है।

उल्लेखनीय है कि जगदलपुर से सिर्फ एक ही अलायंस एयर की फ्लाइट चलती है। जो जगदलपुर को हवाई मार्ग के माध्यम से हैदराबाद और रायपुर को जोड़ती है। सामान्य दिनों में यात्रियों को सप्ताह के सातों दिन इस हवाई सेवा का लाभ मिलता है। ऐसा बताया जा रहा है कि, फिलहाल जगदलपुर से हैदराबाद के लिए यात्रियों की संख्या अच्छी है, लेकिन रायपुर के लिए संख्या में कमी आई है। इसी वजह से सप्ताह में सिर्फ 02 दिन ही रायपुर के लिए फ्लाइट चलाने का निर्णय लिया गया है। जारी समयसारणी के अनुसार रविवार को हैदराबाद-जगदलपुर, जगदलपुर-हैदराबाद, सोमवार को हैदराबाद-जगदलपुर, जगदलपुर-हैदराबाद, मंगलवार को हैदराबाद-जगदलपुर-रायपुर, रायपुर- जगदलपुर-हैदराबाद, बुधवार को अवकाश रहेगा।

नक्सल खौफ को दरकिनार कर मतदाताओं ने किया 75.62 प्रतिशत मतदान

जगदलपुर। बस्तर ने लोकतंत्र की परीक्षा डिस्टिंक्शन से उत्तीर्ण कर ली है। निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण में 20 सीट पर हुए मतदान के आंकड़ें जारी कर दिए है। इसमें नक्सल प्रभावित बस्तर की 12 विधानसभा सीट पर 75.62 प्रतिशत मतदाताओं ने लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए जमकर उत्साह दिखाया है। 2018 के विधानसभा चुनाव में 73.31 प्रतिशत लोगों ने मतदान किया था। इस बार 2.31 प्रतिशत अधिक लोगों ने मतदान किया है।

इसमें नक्सल संवेदनशील क्षेत्र के मतदाताओं ने भी नक्सल डर को दरकिनार करते हुए जमकर मतदान किया। विगत चार वर्ष में जिस तरह से सुरक्षा बल ने बस्तर को सुरक्षित करने में योगदान दिया है, इसका भारी असर पड़ा है। आयोग की ओर से बस्तर में मिनपा, सिलगेर, चांदामेटा सहित 126 नए मतदान केंद्र नक्सलियों के गढ़ माने जाने वाले क्षेत्र में खोले गए थे। इसमें ग्रामीणों ने जमकर उत्साह दिखाते हुए गनतंत्र से आगे बढ़कर गणतंत्र पर भरोसा जताया है।

बस्तर जिले के चांदामेटा में पहली बार मतदान हुआ। गांव के युवा श्याम कवासी ने भी पहली बार मतदान किया। वह गांव में खोले गए नए स्कूल में शिक्षादूत है। कवासी बताते हैं कि यह गांव पूरी तरह से नक्सल प्रभाव में था। दो वर्ष पहले सुरक्षा बल के यहां आने के बाद वह गांव लौटा है। ग्रामीणों का भरोसा भी लोकतंत्र पर बढ़ा है। यहां मुख्यधारा में लौट आए गांव के दो दर्जन पूर्व नक्सलियों ने भी वोट डालकर जनतंत्र को बनाए रखने में अपना योगदान दिया। झीरम गांव में 2013 में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा में हुए हमले के बाद गांव के आसपास आधा दर्जन सुरक्षा बल के कैंप खोले गए हैं। इस बार विस्थापित मतदान केंद्र को गांव में खोला गया। गांव के स्कूल में शिक्षक फूलसिंह कोवाची ने बताया कि मतदान को लेकर ग्रामीणों ने जमकर उत्साह दिखाया है।

मतदान कराकर लौटे मतदान दलों का कलेक्टर नूपुर राशि पन्ना ने प्रशस्ति पत्र देकर किया स्वागत

सक्ती। सक्ती जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों में निर्वाचन कार्य शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न हुआ। पोलिंग बूथों में मतदान के पूर्ण होने के बाद मतदान दलों की वापसी पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती नूपुर राशि पन्ना ने तीनों विधानसभा क्षेत्रों के दल के सभी सदस्यों का स्वागत किया। मतदान दल के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कलेक्टर श्रीमती नूपुर राशि पन्ना ने प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित करते हुए शुभकामनाएं दी। सक्ती विधानसभा क्षेत्र के कुसुमझर मतदान केन्द्र से स्ट्रॉन्ग रूम पहुंची पहली संगवारी दल का भी कलेक्टर ने किया स्वागत

कलेक्टर श्रीमती नूपुर राशि पन्ना ने शासकीय प्राथमिक शाला कुसुमझर की आदर्श संगवारी मतदान केंद्र की महिला मतदान दल के अधिकारियों का शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न कराकर मतदान संग्रहण केन्द्र पहुंचने पर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान करते हुए शुभकामनाएं दी। जिस पर उक्त मतदान दल के पीठासीन अधिकारी ने बताया कि ये उनका पहला मतदान कराने का अनुभव था। जिला प्रशासन के सतत मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण से हमें बहुत मदद मिली। दल के सभी सदस्यों व जिला प्रशासन का भरपूर सहयोग मिला।

स्मृति ईरानी की सभा के दौरान पूर्व सांसद कमला पाटले से सक्ती थाना टीआई की हुई बहस

सक्ती। सक्ती में आयोजित पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की सभा के दौरान हेलीपैड के अंदर जाने को लेकर भाजपा जांजगीर- चांपा लोकसभा क्षेत्र की दो बार सांसद रही एवं भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चे की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती कमला पाटले के साथ सक्ती थाना टीआई विवेक शर्मा की बहस हो गई, तथा श्रीमती कमला पाटले हेलीपैड के अंदर जाना जा रही थी, किंतु सक्ती थाना टीआई विवेक शर्मा ने उन्हें कहा कि श्रीमती स्मृति ईरानी जी ने अंदर आने से सभी को मना किया है, तथा मैं उन्हें स्वयं पैदल हेलीपैड से लेकर मंच तक जा रहा था किंतु उन्होंने यहां की स्थिति को देखते हुए गाड़ी मंगाई और उसमें बैठकर वे जाएंगी, जिस पर पूर्व सांसद कमला पाटले भड़क गई एवं उन्होंने कहा कि आप तमीज से बात कीजिए तथा हमारे कार्यकर्ता आपको औकात बता देंगे, जिस पर सक्ती थाना टीआई विवेक शर्मा ने भी कहा कि आप मुझे कुछ मत बोलिए, हमे स्मृति ईरानी जी ने जो कहा है मैं उसका पालन कर रहा हूं, जिस पर नेता और अधिकारी के बीच काफी तनातनी की स्थिति बनी रही।

जिला अस्पताल से हत्या का आरोपी फरार

ज्वेलर्स की हत्या कर लूटी थी ज्वैलर्स शॉप

दुर्ग। दुर्ग जिला अस्पताल से लूट और हत्या का आरोपी अभिषेक झा चकमा देकर फरार हो गया। वह केंद्रीय जेल दुर्ग में बंद था। मंगलवार रात उसे जिला अस्पताल दुर्ग में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। बुधवार रात 4 हथियारबंद युवक वहां पहुंचे और उसे अपने साथ भगाकर ले गए।

ड्यूटी पर तैनात जेल के आरक्षक से मिली जानकारी के अनुसार, जिला अस्पताल के कैदी वार्ड में हत्या और लूट के आरोपी अभिषेक झा का इलाज चल रहा था। बुधवार रात करीब 9.30 से 10 बजे के बीच 4 लोग हथियार के साथ पहुंचे। उन्होंने अभिषेक को भगाने का प्रयास किया।

जब आरक्षक ने उसका विरोध किया तो उन्होंने उसके साथ मारपीट की। जब दूसरा जेल प्रहरी वहां आया तो उन लोगों ने उनके ऊपर कट्टा टिका दिया। इसके बाद उन लोगों ने अभिषेक झा को साथ लिया और वहां से फरार हो गए। दुर्ग पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए कई टीमों को लगाया है। अभी तक आरोपी पकड़ा नहीं जा सका है।

जेल में मोबाइल नेटवर्क पर नहीं दिया जा रहा ध्यान

सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय जेल दुर्ग में अपराधियों को मोबाइल फोन आसानी से उपलब्ध है। जेल प्रबंधन द्वारा महीने का किराया लेकर उन्हें मोबाइल दिया जाता है। इससे वो जेल के अंदर बैठे-बैठे ही अपना गैंग संचालित कर रहे हैं। इससे पहले भी जेल के अंदर का वीडियो कुछ आरोपियों ने वायरल किया था। आरोप है कि अभिषेक झा के पास भी मोबाइल फोन था। उसने जेल के अंदर से अपने लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती होने की खबर दे दी थी। इसके बाद योजनाबद्ध तरीके से वो वहां से फरार हो गया।

अमलेश्वर में ज्वेलर्स की गोली मारकर की थी हत्या

अभिषेक झा उत्तर प्रदेश का पेशेवर अपराधी है। वो लगभग एक साल पहले अपने साथियों के साथ अमलेश्वर में समृद्धि ज्वेलर्स को लूटने गया था। इस दौरान उसने कट्टे से गोली मारकर ज्वेलर्स की हत्या कर दी थी। अभिषेक के खिलाफ दुर्ग, रायपुर समेत अन्य जिलों में कई गंभीर मामले दर्ज हैं।

दूसरी बार हुआ है फरार

अभिषेक झा इतना शातिर अपराधी है कि वो अधिक दिन तक जेल में नहीं रहता। सजा के दौरान ये दूसरी बार अभिरक्षा से भागा है। इससे पहले वो रायपुर में पेशी के दौरान कोर्ट से फरार हो गया था। उसने फरारी के दौरान ही अम्लेश्वर में 3 साथियों के साथ लूट और हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। इसके बाद रायपुर और दुर्ग की पुलिस ने मिलकर उसे उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गिरफ्तार

जिले में तीन लाख से ज्यादा लोग आयुष्मान कार्ड से वंचित

महासमुंद। जिले में आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य 11 लाख रखा गया है, लेकिन अब तक सात लाख 50 हजार लोगों ने ही आयुष्मान कार्ड बनाया है। ज्यादातर बच्चों और बुजुर्गों का कार्ड नहीं बन पाया है। सैकड़ों आयुष्मान कार्ड च्वाइस सेंटर में रखे हुए हैं, लेकिन कई हितग्राही अब तक लेने नहीं पहुंच रहे हैं। कई हितग्राही का प्लास्टिक कार्ड अब तक नहीं पहुंचा है। जिले में ऐसे कई आवेदक हैं, जिन्होंने सालभर पहले पंजीयन कराया था, लेकिन अब तक उन्हें कार्ड नहीं मिला है, वे च्वाइस सेंटर से कागज के कार्ड निकालकर ही अपना काम चला रहे हैं। च्वाइस सेंटर के माध्यम से लोगों को कार्ड वितरण की योजना बनाई गई थी, लेकिन कई च्वाइस सेंटर में ही कार्ड बनकर नहीं पहुंचे हैं।

आयुष्मान योजना के तहत लोगों को निजी अस्पताल में बीपीएल कार्डधारियों को 5 लाख रूपए तक निःशुल्क उपचार व एपीएल कार्डधारी को 50 हजार रूपए तक निःशुल्क उपचार कराने की सुविधा दी गई है। निजी अस्पताल में भी राशनकार्ड दिखाकर तत्काल योजना का लाभ ले सकते हैं। तीन लाख से ज्यादा लोगों का सत्यापन नहीं हो पाया है। इससे जरूरतमंद लोग लाभ लेने से वंचित हो रहे हैं। आयुष्मान कार्ड प्रभारी ओपी धुर्वधर ने बताया कि ज्यादातर बच्चों व बुजुर्गों का सत्यापन ही नहीं हुआ है, लेकिन बच्चों के कार्ड बनाने के लिए भी व्यवस्था की गई है।

104 पर कर सकते हैं शिकायत

आयुष्मान कार्ड के बाद यदि कोई संबद्ध अस्पताल पैसे लेता है तो कार्रवाई का भी प्रावधान है। 104 नंबर डायल कर शिकायत की जा सकती है। आयुष्मान कार्ड के तहत कई उपचार सेवाएं शामिल नहीं किए जाने से भी लोगों को दिक्कत होती है। लोग अस्पताल तो पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें पैसा भुगतान करना पड़ जाता है। आयुष्मान भारत योजना को लेकर चुनाव के घोषणा पत्र में आम जनता से वादे किए गए हैं। ऐसे लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ देने के लिए राशि बढ़ सकती है जिससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और लोग बड़े बीमारियों का उपचार भी करा सकेंगे। वर्तमान में आयुष्मान कार्ड के तहत कई बीमारियों का उपचार नहीं होने से लोग मायूस हैं।

शराब दूकानों पर हुई असामान्य बिक्री

महासमुंद। छग विधानसभा निर्वाचन-2023 के मद्देनजर कलेक्टर प्रभात मलिक द्वारा आबकारी विभाग को जिले की समस्त देशी, विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों की सतत जांच तथा कड़ी निगरानी रखने एवं अनियमितता पाए जाने पर कार्यवाही के निर्देश दिए गए थे। उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में आबकारी विभाग जिला महासमुंद द्वारा मदिरा दुकानो मे दैनिक मदिरा स्कंध पंजी का अद्यतन संधारण सुनिश्चित किया जा रहा है। मदिरा के आमद, भंडारण तथा दैनिक विक्रय पर प्रभारी अधिकारियों के माध्यम से कड़ी निगरानी रखी जा रही है। मदिरा दुकानों में स्थापित सीसी टीवी कैमरों के सुचारू संचालन तथा न्युनतम 15 दिवस का बैकअप संधारण सुनिश्चित किया जा रहा है एवं तकनीकी समस्या आने पर तत्काल निरीक्षण किया जा रहा है।

जिले के कार्यपालिक स्टॉफ द्वारा औसत विक्रय मात्रा की तुलना में 30 प्रतिशत या अधिक बिक्री वाली मदिरा दुकानों का गहन निरीक्षण किया जा रहा है।

संजारी बालोद विधानसभा क्षेत्र मुजगहन के ग्रामीणों ने चुनाव का किया बहिष्कार

शासन प्रशासन से नाराज ग्रामीणों ने वोटिंग से बनाई दूरी

बालोद। जिले के संजारी बालोद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत स्थित ग्राम मुजगहन के ग्रामीणों ने ज्यादातर हिस्सा नहीं लिया और लोकतंत्र के मतदान त्यौहार से वँचित नजर आए । ग्राम मुजगहन में केंद्र क्रमांक 112 में कुल 1080 मतदाता है जहाँ मात्र 4लोगों ने वोट कर लोकतंत्र के त्यौहार में मतदान कर जागरूकता का परिचय देते नजर आय। तो वहीं ग्रामीणों ने शासन-प्रशासन के खिलाफ नाराजगी व्यक्त करते हुए वोटिंग से दूरी बनाई हुई है सुबह 8:00 बजे से शुरू हुई और शाम 5:00बजे तक कुल मतदान केंद्र में महज 4 वोट डालें गए है। इस तरह गाँव के कुल 1076लोगों ने अपने मताधिकार का उपयोग नहीं किया और लोकतंत्र के इस पर्व का हिस्सा नहीं बन पाए।

ग्रामीण मुकेश साहू, नेवेन्द्र साहू, देव चरण दास मानिकपुरी ने बताया की गांव की ही एक व्यक्ति मोहम्मद हनीफ खान द्वारा गांव के अलग-अलग जगह करोड़ों की जमीन पर अवैध कब्जा का किया गया है। जिसके चलते कई बार प्रशासन से शिकायत कर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ जांच व कार्यवाही नहीं होने पर चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दी गई थी। जिसके चलते ग्रामीणों द्वारा मतदान नहीं कर विरोध जाहिर किया गया। वहीं ग्रामीणों ने यह भी बतलाया की कुछ मामलों में जाँच कर तत्काल कार्यवाही की गई लेकिन अधिकांश जमीन के मामले आज भी लंबित पड़े हुए है।

वहीं कुछ दिन पूर्व ही पंचायत के तमाम पंच और सरपंच ने प्रशासन को अपने पद से इस्तीफा दिया गया था इसके बावजूद ग्रामीण और प्रशासन के बीच समझौता नहीं हो पाया और इसकी नाराजगी ग्रामीणों ने मतदाता मतदान ना कर जाहिर किया जिसके कारण सुबह से शाम तक महज 4लोगों ने ही मतदान किया बाकी किसी भी ग्रामीण ने अपने मत का उपयोग जनप्रतिनिधि चुनने के लिए नहीं किया। हालांकि प्रशासन की टीम तहसीदार ,जनपद सीईओ लगातार लोगों को समझाने का प्रयास करते नजर आए लेकिन ग्रामीण है कि समझ ही नही रहे थे जो अपनी मांग को लेकर अड़े हुए थे जिसका व्यापक असर सीधे मतदान केंद्र पर देखने को मिला।

सरपँच उमेश्वरी नेताम ने बताया कि हमारे गांव का एक व्यक्ति हनीफ से हम लोगो की लड़ाई जमीन को लेकर चल रही है जिसका निराकरण प्रशासन द्वारा आज तक नही हो पाई लिहाजा हम लोगो ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया है कोई भी व्यक्ति वोट नही कर रहा है।

अबूझमाड़ मलखंब के खिलाड़ी अमेरीका गॉट टैलेंट में करेंगे प्रर्दशन

नारायणपुर। छत्तीसगढ़ के धूर नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिले के अबुझमाड़ के मलखंब खिलाडि़यों को अमेरिका गॉट टैलेंट में प्रर्दशन करने के लिए आमंत्रित किया गया है। अमेरीका गॉट टैलेंट सीजन-19 के प्रोड्यूसर जॉन एवं लुके के साथ मलखंब कोच मनोज प्रसाद से संपर्क किया और दोनों के बीच बातचीत हुई है। इससे पूर्व आपको याद होगा कि कुछ दिनों पूर्व सोनी टीवी द्वारा प्रसारित कार्यक्रम इंडियाज गाट टेलेन्ट में अबूझमाड़ के मलखंब खिलाडियों ने अपना जौहर दिखते हुए छत्तीसगढ़ का नाम रौशन किया था। यह पहला अवसर नहीं है जब अबूझमाड़ के मलखंब खिलाडि़यों ने विदेशों में पहचान बनाने जा रहें हैं, इससे पहले विश्व मलखंब चैंपियनशिप 2023 भूटान में आयोजित किया गया था। विश्व मलखंब चैंपियनशिप में अबूझमाड़ के खिलाडि़यों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत के लिए एक स्वर्ण पदक जीतकर देश और प्रदेश का मान बढ़ाया था।

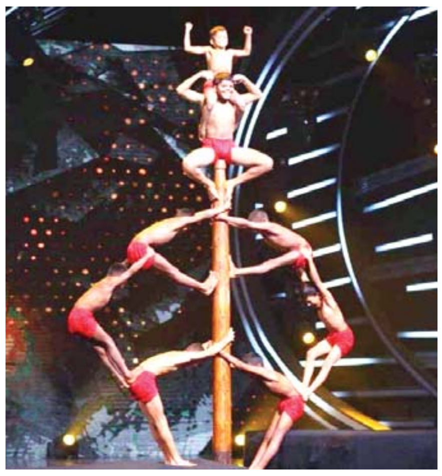

अबुझमाड़ मलखंब के प्रशिक्षक मनोज प्रसाद ने बताया कि अमेरीका गॉट टैलेंट सीजन-19 का हिस्सा बनने के लिए दो मीटिंग हो चुकी है। दिसंबर 2023 में अंतिम बैठक ऑनलाइन होगी, इसके बाद खिलाडियों के जाने का फैसला हो जाएगा। उन्होंने बताया कि इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन-10 में मलखंब खिलाडि़यों ने खिताब अपने नाम किया था। जिसके बाद अमरीका गॉट टैलेंट के प्रोड्यूसर ने इसमें दिलचस्पी दिखाई है।

उल्लेखनीय है कि नक्सलियों का गढ़ कहे जाने वाले नारायणपुर जिले का अबूझमाड़ देश का एक ऐसा इलाका है, जहां विकास की कोई किरण कोसों दूर तक नहीं दिखती, उसके बावजूद यहां के बच्चे अभाव के बीच एक अच्छे खिलाड़ी बन कर निखर रहे हैं। 15 अगस्त 2017 को नारायणपुर के रामकृष्ण मिशन ग्राउंड में अपने दो साथियों और कुछ बच्चों के साथ पहली बार मलखंब का प्रदर्शन के दिशा में शुरुआती प्रयास में बच्चों की रुचि बढने लगी और उन्होंने मलखंब खेल के कठिन अभ्यास की ओर बच्चों को मोड़ दिया। अबूझमाड़ के बच्चे मलखंब जैसे साहसिक और पारंपरिक खेल में पारंगत हो चले हैं।

प्रदेश की जनता पर पहले ही 89000 करोड़ कर्ज, अब और बढ़ेगा

- **चुनावी वादें भारी पड़ रहे राजकोष पर**
- **हर साल देना पड़ता है 6 हजार करोड़ ब्याज**

रायपुर। चुनाव के वक्त राजनीतिक दल बड़े-बड़े वादे पूरा करने से बाज नहीं आते। कर्जमाफी और मुफ्त की योजनाएं जनता को रिझाने का एक बड़ा तरीका बन रही हैं। हालांकि राज्य के की कमाई में ज्यादा वृद्धि दिखाई नहीं देती। ऐसे में राज्य कर्ज तले दबते चले जा रहा है। प्रदेश में चुनाव से पहले भाजपा और कांग्रेस दोनों ने बड़े-बड़े वादे किए हैं। कांग्रेस ने कर्जमाफी, महिलाओं को हर साल 15 हजार की मदद, गैस सिलिंडर पर सब्सिडी, भूमिहीन मजदूरों को 10 हजार रुपये, पराली और तेंदू पत्ते की खरीद, ओपीएस जैसे तमाम लोकलुभावन वादे किए हैं। वहीं बात करें कर्ज की तो राज्य पर कुल 89 हजार करोड़ रुपये बकाया है। प्रदेश का सालाना बजट विधानसभा में दी गई जानकारी के मुताबिक लगभग 1 लाख करोड़ रुपए है। इस हिसाब से बजट में 40 फीसदी का इजाफा हो जाएगा।

वादों पर 40 हजार करोड़ खर्च हर साल

प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य को वर्तमान में करीब 6 हजार करोड़ रुपये का ब्याज प्रतिवर्ष चुकाना होता है। अगर 2023 के चुनावी वादे लागू हुए तो राज्य का कर्ज और तेजी से बढ़ेगा। अगर कांग्रेस अपने सभी वादे पूरा करती है तो कम से कम साल का 40 हजार करोड़ रुपये खर्च होगा।

वही भाजपा की सरकार अगर बनती है तो भी इसी के पास वादे वाली योजनाओं की लागत आएगी। हालांकि भाजपा ने कुछ स्कीम जैसे महतारी वंदन योजना जिसमें हर साल 12000 रुपए महिलाओं को उनके खाते में देने की बात कही है वह केन्द्र के सहयोग से चालू करने की बात कही है।

पुरानी पेंशन योजना से 22 हजार करोड़ का बोझ

कांग्रेस सरकार ने वापसी पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने का वादा किया है। इस योजना से राज्य पर भारी बोझ पड़ने वाला है। इसमें हर साल करीब 22 हजार करोड़ रुपये खर्च होगा। किसानों की कर्जमाफी भी कांग्रेस के वादों में शामिल रहती है। 2019 में 19 लाख किसानों का कर्ज माफ करने में 9500 करोड़ रुपये का खर्च आया था। वहीं अब रजिस्टर्ड किसानों की संख्या भी काफी बढ़ गई है। अगर 3.55 लाख भूमिहीन मजदूरों को हर साल 10 हजार करोड़ रुपये दिया जाएगा तो इसमें 355 करोड़ रुपये प्रति साल का खर्च आएगा।

कर्जमाफी में लगेंगे करोड़ों

स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का कर्जमाफ किया जाएगा तो 250 करोड़ रुपये लगेंगे। इसके अलावा अन्य कर्जमाफी में भी 726 करोड़ रुपये का बोझ पड़ सकता है। चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा है कि पहली कैबिनेट बैठक के दौरान ही किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा था कि राजीव गांधी न्याय योजना के तहत किसानों पर 23 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। पराली के लिए भी किसानों को अच्छी कीमते मिलेंगी। कांग्रेस का वादा है किसानों से 20 क्विंटल तक पराली की खरीद एमएसपी पर की जाएगी। इस साल की बात करें तो पराली खरीद में 8700 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

महिलाओं को 15 हजार देने में 15385 करोड़ का बोझ

वहीं महिलाओं को हर साल 15 हजार रुपये देने में 15385 करोड़ रुपये हर साल खर्च होने का अनुमान है। इसके अलावा भी कांग्रेस ने कई वादे किए हैं। इसमें 200 यूनिट तक फ्री बिजली, किसानों को फ्री बिजली, केजी से पीजी तक फ्री एजुकेश, तेंदू पत्ते पर बोनस आदि शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में 12.94 लाख परिवार तेंदू पत्ते इकट्ठा करते हैं। इस हिसाब से इपर 517 करोड़ रुपये हर साल खर्च होंगे। वहीं बोनस के भी 776 करोड़ रुपये देने होंगे। इसके अलावा गरीबों के मुफ्त इलाज पर भी बड़ी रकम खर्च होगी।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक- गुलाब दास दीवान, द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि. (छ.ग.) भवन, प्रेस काम्पलेक्स रजबंधा मैदान रायपुर (छ.ग.) से मुद्रित एवं ग्राम-पोस्ट-पवनी, तहसील-बिलाईगढ़, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.), 493338 से प्रकाशित। RNI NO. CHHHIN/2022/83778 सम्पादक- गुलाब दास दीवान, मो. 9294743139